twitter.com/divyadelhi facebook.com/divyadelhi infodivyadelhi@gmail.com Editor: Rajesh Chauhan

RNI No. DELHI/2013/54397

दिव्य दिल्ली

divyadelhi.com | रविवार, 20 जुलाई, 2025 | वर्ष: 12, अंक: 244, पृष्ठ: 08 | ₹ 05/- | दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

छोटे राज्यों का विकास जरूरी: अमित शाह

'पीएम मोदी छोटे और पूर्वी राज्यों के विकास को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे'

देहरादून/एजेंसी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2047 में विकसित भारत की कल्पना तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक छोटे व पूर्वी राज्यों का विकास नहीं होता। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छोटे और पूर्वी राज्यों के विकास को लेकर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। अमित शाह ने घोषणा की कि 2027 में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव-2025 में जनसभा के दौरान यह कहा। उन्होंने कहा कि जब भी मैं उत्तराखंड आता हूं, एक नई ऊर्जा लेकर वापस जाता हूं क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में निवासरत सारे देवी-देवताओ और आध्यात्म की अलख जगाने वाले संतों का आशीष प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक ओर पर्वत की चोटियां पूरी दुनिया को आध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करती हैं, वहीं यहां निवासरत साधु संत भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यहां की नदियां आधे भारत को सिंचाई और पीने का पानी दे रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में निवेश और उद्योगों की स्थापना सरल कार्य है लेकिन छोटे से उत्तराखंड की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में एक लाख करोड़ का उद्योगों पर निवेश के साथ ही 81 हजार से अधिक का रोजगार सृजित करवाना बेहद कठिन कार्य हैं और पुष्कर सिंह धामी व उनकी टीम ने अत्यंत कठिन कार्य पूरा किया। इसके लिए धामी और उनकी टीम को साधुवाद। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन भी स्थापित किया है। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है। नीतियों में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ ही उत्तराखंड के समग्र विकास का खांचा खींचा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के संघर्ष के दौरान कांग्रेस ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के साथ ही झारखंड व छत्तीसगढ़ को अलग राज्य घोषित किया।

अटल विहारी वाजपेयी ने तीन राज्य बनाए और आज मोदी सरकार इन राज्यों को विकास की नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने 5 योजनाओं का लोकार्पण व 13 योजनाओं का शिलान्यास भी किया।

'25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचा दिया'

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिथक को तोड़ते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचा दिया है। मोदी सरकार गरीबों को पांच किलो मुफ्त अनाज देकर खाद्य सुरक्षा प्रदान कर रही है, साथ ही 55 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान कर रही है। इस दौरान 16 करोड़ घरों में पहली बार नल से जल पहुंचा, 12 करोड़ घरों में शौचालय, 13 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की सुविधा प्रदान की गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में तीन करोड़ घरों में पहली बार बिजली पहुंची, चार करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, लेकिन विकसित उत्तराखंड के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है।

शाह ने कहा- 2027 में भारत बनेगा तीसरी आर्थिक शक्ति

देहरादून

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में भी उद्योग स्थापित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और विजन में दूरदर्शिता के साथ विकास का नया खाका तैयार किया है।

अमित शाह ने रुद्रपुर में आयोजित निवेशक उत्सव-2025 के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में विकास का खाका खींचते हुए हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई दस साल में 60 प्रतिशत बढ़ी है, इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आठ लाख किमी सड़कें बनी हैं। 333 जिलों में सुविधाजनक वंदे भारत ट्रेन पहुंच चुकी है। दस सालों में 45 हजार किमी रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया, 88 नए हवाई अड्डे बने साथ ही इनलैंड वाटर वे कारगो में 11 गुना बढ़ोत्तरी हुई है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अटल जी देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़ गए थे, मोदी इसे चौथे नंबर पर ले आए हैं। अब 2027 में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक समय में कहा जाता था कि आधारभूत सुविधाएं विकसित करते हुए, देश के गरीबों का कल्याण संभव नहीं है।

कांवड़ मेला : अब तक ढाई करोड़ शिव भक्तों ने भरा गंगाजल

हरिद्वार/एजेंसी

हरिद्वार में श्रावण मास के विश्वप्रसिद्ध कांवड़ मेले को शुरू हुए नौ दिन बीत चुके हैं। इस दौरान करीब ढाई करोड़ कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भर कर अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान किया है। शिवभक्तों के हुजूम से हरिद्वार पूरी तरह भगवामय हो गया है। आज से हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की धूम शुरू हो गयी है। हरिद्वार में भारी वाहनों के प्रवेश पर बीती रात से ही प्रतिबंध लग चुका है। स्थाई बस अड्डा भी बंद कर दिया गया है। शहर में चारों ओर कांवड़ियों का ही कब्जा है। कांवड़ियों द्वारा रंग बिरंगी सजी हुई कांवड़ रूपी झांकियों से शहर में उत्सव का माहौल है। पुलिस प्रशासन द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, शनिवार शाम छह बजे तक 48 लाख कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगाजल भरकर अपने अभीष्ट शिवालयों के लिए प्रस्थान किया है। पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि कांवड़ मेला शुरू होने के बाद से शनिवार शाम तक 02 करोड़ 48 लाख 90 हजार कांवड़िए जल भरकर अपने गंतव्यों को रवाना हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन की बुलेटिन के मुताबिक आज गंगा में डूब रहे 22 कांवड़ियों को एसडीआरएफ व सेना की टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया। शनिवार को खोए हुए 112 लोगों में से 94 को पुलिस ने ढूंढकर परिजनों से मिलाया। कांवड़ियों की भारी भीड़ के बावजूद हरिद्वार जनपद में कानून व यातयात व्यवस्था सामान्य रही। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोभाल ने कहा हम पूरी तरह से तैयार हैं और मौके पर जाकर हालात का निरीक्षण कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, गाड़ियां पार्क हो रही हैं, बैरागी कैंप शाम तक काफी हद तक भर जाएगा। हमने उसके बगल में दक्ष पार्किंग तैयार किया है। रूट डायवर्जन प्लान अच्छे से काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा सुचारु रूप से संपन्न होगी। सब कुछ अनुमान के मुताबिक चल रहा है। अभी तक कोई व्यवधान नहीं आया है। इस बार शिव भक्त श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ है। कांवड़ मेला क्षेत्र को 9 ड्रोन कैमरों से कवर किया गया है। एटीएस की 2 टीमें काम कर रही हैं, डॉग स्क्वॉड भी मौजूद है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की।

देश की खाद्य सुरक्षा में हमारे अन्नदाताओं की भूमिका अमूल्य: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली/एजेंसी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने शनिवार को अपने गुजरात के दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में हमारे अन्नदाताओं की भूमिका अमूल्य है। सरकार हर स्तर पर किसानों के साथ है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि गिरनार अपनी उच्च उपज क्षमता के कारण, गिरनार 4 और 5 पुरानी किस्मों की तुलना में न्यूनतम 500 किग्रा/हेक्टेयर अतिरिक्त उपज प्रदान करती हैं। 4.63 मिलियन क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन से 15.45 मिलियन क्विंटल अतिरिक्त मूंगफली की उपज हुई है, जिससे पिछले तीन वर्षों में किसानों की अनुमानित अतिरिक्त आय 11,221.33 करोड़ रुपये हो गई है। अकेले गिरनार 4 से अतिरिक्त आय 6500 करोड़ रुपये से अधिक है। गुजरात यात्रा के दौरान शिवराज सिंह जूनागढ़ जिले के मानेकवाड़ा गांव पहुंचे, और मूंगफली के खेत में उतरे। साथ ही, वहां के मेहनती किसानों से सीधा संवाद किया।

हमारी लड़ाई घुसपैठ के खिलाफ: सीएम हिमंत

गुवाहाटी/एजेंसी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यह विवाद असम में कथित घुसपैठ, भाषायी पहचान और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर है। शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए हिमंत बिस्व सरमा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'हम अपने ही लोगों से नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सीमा पार से हो रही घुसपैठ के खिलाफ है, जो असम की जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ रही है। कई जिलों में हिंदू अब अपने ही घर में अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बाहरी आक्रमण माना है' उन्होंने यह भी कहा कि, 'यह कोई राजनीतिक बयान नहीं, हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बाहरी आक्रमण माना है। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीति बना देते हैं।' सीएम सरमा ने कहा कि असम में सभी भाषाएं और समुदाय साथ रहते हैं, लेकिन सीमाओं और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा जरूरी है।

सीएम ममता बनर्जी का वार

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'बांग्ला भारत की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और असम में भी इसका बड़ा स्थान है। लेकिन भाजपा असम में बंगाली भाषियों को निशाना बना रही है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक और विभाजनकारी है।' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार असम में बांग्लाभाषियों को डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है, उनकी भाषा और पहचान को खत्म कर रही है।

बहुसंख्यक आबादी के कारण मिल रही सुरक्षा: किरेन

नई दिल्ली/एजेंसी

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति और उनकी सुरक्षा की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां अल्पसंख्यक पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक अल्पसंख्यक हूं। अगर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश में होते, तो शायद आज शरणार्थी होते। लेकिन भारत में हर अल्पसंख्यक और आदिवासी अपने ही देश में सुरक्षित है, क्योंकि यहां की बहुसंख्यक हिंदू आबादी स्वभाव से सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष है।

बहुसंख्यक आबादी के कारण मिल रही सुरक्षा

एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान रिजिजू ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को जो स्वतंत्रता और सुरक्षा मिल रही है, वह यहां की बहुसंख्यक आबादी के कारण है। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक एक भी ऐसा मामला नहीं देखा जिसमें किसी अल्पसंख्यक ने यह कहा हो कि उसे भारत छोड़ना है क्योंकि उसे यहां कुछ नहीं मिल रहा।

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

रिजिजू ने अपने बयान में कांग्रेस पर गलत प्रचार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थित वामपंथी सोच वाले लोग यह लगातार प्रचार कर रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। रिजिजू ने कहा कि ऐसा नैरेटिव देश के लिए नुकसानदायक है। इसके साथ ही रिजिजू ने पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है। वाले बयान पर कहा कि भारत एक कानून का पालन करने वाला, धर्मनिरपेक्ष और संविधान आधारित देश है, जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों कानून की नजर में बराबर हैं।

भारत-अमेरिका ने व्यापार समझौते पर पांचवें दौर की वार्ता पूरी की

नई दिल्ली/एजेंसी

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर जल्द सहमति बन सकती है। भारत और अमेरिका की टीमों ने बीटीए के लिए वाशिंगटन में 17 जुलाई को पांचवें दौर की वार्ता पूरी कर ली है।

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच बीटीए के लिए पांचवें दौर की बातचीत पूरी हो गई है। दोनों देशों के अधिकारियों की टीमों के बीच यह वार्ता 17 जुलाई को वाशिंगटन में सपन्न हुई जो चार दिनों 14 से 17 जुलाई तक चली। भारत इस्पात और एल्युमीनियम पर (50 फीसदी), वाहन (25 फीसदी) और अन्य उत्पादों पर लगे अतिरिक्त शुल्क (26 फीसदी) को हटाने की मांग कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय टीम वापस आ रही है। भारत के मुख्य वातार्कार और वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल वार्ता दल का नेतृत्व कर रहे हैं।

मोदी के नेतृत्व में भारत बना चौथी आर्थिक महाशक्ति: सैनी

चंडीगढ़/एजेंसी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत और विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक विकसित राष्ट्र की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। 2014 के बाद भारत ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' संकल्प में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाते हुए केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढेगा। मुख्यमंत्री जिला जींद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने अग्रसेन धर्मशाला का उद्घाटन तथा नंदी एवं कामधेनु गौशाला का भूमि पूजन किया। उन्होंने धर्मशाला के लिए 31 लाख रुपये देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक सशक्त पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत एक दिन आर्थिक महाशक्ति बनेगा, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गई है, विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव हो सकी है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों के पास देश के विकास का कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं था।

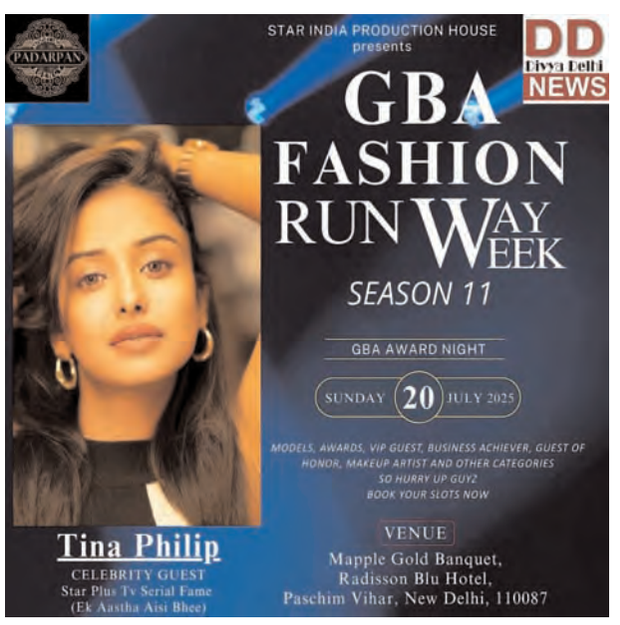

कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जा रहा, उन्हें उपद्रवी बोला जाता है : योगी आदित्यनाथ

एजेंसी

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्री पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना से यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोला जाता है। यह मानसिकता हर प्रकार से भारत की विरासत और आस्था को अपमानित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के अन्तिम दिन यहां राजघाट स्थित वसंता महिला महाविद्यालय में आयोजित बिरसा मुंडा की विरासत, आदिवासी सशक्तीकरण और राष्ट्रीय आंदोलन विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने और जातीय संघर्ष को हवा देने वालों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बारे में समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कांवड़ यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा, आज कांवड़ यात्री अपनी भक्ति भावना से 200, 300, 400 किलोमीटर तक कांवड़ उठाकर हर-

हर बम बोलते हुए चले जाते हैं, लेकिन उनका भी मीडिया ट्रायल होता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोला जाता है। यह मानसिकता हर प्रकार से भारत की विरासत और आस्था को अपमानित करने का काम कर रही हैं। यही लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर जातीय संघर्ष फैलाने का काम करते हैं....। समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज के बीच विघटन पैदा कर लोगों को मुख्यधारा से अलग करने का काम करते हैं। इनके ऐसे ही कारनामे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती का संदेश देते हुए आम लोगों को भी सतर्क किया। उन्होंने एक घटना का उल्लेख कर कहा कि दो-तीन साल पहले ऐसे ही एक घटना हुई थी। एक आगजनी की घटना में एक व्यक्ति केसरिया भगवा गमछा ओढ़े था, बीच में अचानक गमछा निकलने पर उसके मुंह से निकला या अल्लाह...। समाज की एकता में ऐसे लोग बाधक है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए।

ऐसे लोग बातों से नहीं मानते-

मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का महीना चल रहा है। इससे पहले मुहर्रम था, हमने नियम बना दिये थे कि ताजिये की लंबाई सीमित रखें। इससे बिजली,पेड़ की टहनी को नुकसान पहुंचता था। मुहर्रम पर नियम नहीं मानने पर जौनपुर में घटना हो गई । ताजिया को इतना ऊंचा किया कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर तीन लोग मारे गए। बाद में उपद्रव हुआ, तो मैंने कहा लाठी मारो इनको, बातों से नही मानेंगे। इसका किसी ने विरोध नही किया।

स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला साफ्टवेयर इंजीनियर फरीदाबाद से हिरासत में

एजेंसी

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकियां देने के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिरासत में लिया है। आरोपित की पहचान फरीदाबाद निवासी शुभम दुबे के रूप में हुई है। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने इसकी जानकारी दी। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने शुक्रवार को बताया कि बीती 14, 15 व 16 जुलाई को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को मेल भेजकर दरबार साहिब को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मेल में दरबार साहिब के अलावा दिल्ली के स्कूलों और तमिलनाडु की कई संस्थाओं की जिक्र था। भुल्लर ने बताया कि जांच में तमिलनाडु के कई अधिकारी भी पंजाब पुलिस के संपर्क में हैं। इस तरह के कई ई-मेल बीते समय में तमिलनाडु में भी सर्कुलेट हुई हैं। ई-मेल में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके), दक्षिण राज्यों के लोगों के नाम ही प्रयोग किए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी शुभम दुबे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो दो कंपनियों में जॉब के बाद अब बेरोजगार है। इस मामले में पुलिस को कुछ तकनीकी सबूत भी मिले हैं। पूछताछ में अगर उसकी संलिप्तता पाई गयी, तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। भुल्लर ने बताया कि ई-मेल भेजने के लिए आरोपित डार्कनेट का प्रयोग कर रहे हैं, जिसक कारण आईपी एड्रेस अन्य-अन्य देशों के आ रहे हैं। हिरासत में लिए गए आरोपित शुभम से पूछताछ कर पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह कोई अकेला साइबर हमला था या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क या कट्टरपंथी साजिश है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला दल ने 19,500 फीट पर किए दर्शन, भक्ति में डूबे श्रद्धालु

देहरादून। 19,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत के मानसरोवर यात्रा के पहले दल ने आज भगवान शिव के दर्शन किए। कैलाश की पहली झलक से श्रद्धालुओं की आंखों से अश्रु बह निकले और वे हर-हर महादेवके उद्घोष करने लगे। इस दल में देश के 11 राज्यों से आए कुल 49 श्रद्धालु शामिल हैं। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से हुई, जो पिथौरागढ़, गूंजी और लिपुलेख होते हुए चीन के तकलाकोट तक पहुंची। दर्शन के बाद यात्री आज भारत लौट आएंगे और अपनी यात्रा के फोटो भी साझा किए। यात्री नरेंद्र ने बताया कि यात्रा भले ही कठिन रही, लेकिन हर कदम पर भगवान शिव की ओर बढ़ना सुखद अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि डोल्मा पास की चढ़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण थी, कईयों को थकान और ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन भक्ति और आस्था ने उन्हें हिम्मत दी। यात्री ऊं नमः शिवाय का जप करते हुए आगे बढ़ते रहे। यात्री नागपाल ने बताया कि कैलाश दर्शन के बाद मानसरोवर झील के दर्शन हुए, जहां पवित्र जल में उभरते दृश्यों ने ऐसा अहसास कराया मानो हिमालय भी शिव के समक्ष नतमस्तक हो। झील के किनारे हवन-यज्ञ, दीप प्रज्वलन और भोलेनाथ का आह्वान किया गया, साथ ही देश की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की गई। प्रथम दल के लाइजनिंग ऑफिसर संजय गुज्याल ने बताया कि सभी यात्री दर्शन के बाद स्वस्थ्य हैं और भारत की ओर लौट रहे हैं। वे अपने को सौभाग्यशाली मानते हुए शिव-शिव का जाप कर रहे हैं।

बंगाल जूझ रहा है तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से : मोदी

दुर्गापुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर आने से पहले राज्य की ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सत्तारूढ़ पार्टी के कुशासन से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के दौरे पर आने से कुछ घंटे पहले यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि भगवा पार्टी राज्य का विकास कर सकती है। पूर्वी बर्धमान के औद्योगिक शहर पहुँचने से पहले श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स मंच पर कहा, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से जूझ रहा है। लोगों का मानना है कि केवल भाजपा ही विकास कर सकती है। उन्होंने लोगों से भाजपा की उस रैली में शामिल होने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, 18 जुलाई को दुर्गापुर में एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच आने का बेसब्री से इंतज़ार है। मैं विभिन्न कार्यों की आधारशिला रखूँगा और 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करूँगा।

प्रधानमंत्री आज राज्य के विभिन्न जन-उन्मुख परियोजनाएँ तेल और गैस, बिजली, रेलवे और सड़क का उद्घाटन एवं आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा शहर के आसपास के निकटवर्ती स्थल से भाजपा की रैली के लिए रवाना होने से पहले नेहरू स्टेडियम में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भाजपा का लक्ष्य 2026 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटाना है। श्री मोदी का यहा दौरा राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उम्मीद है कि इससे स्थानीय पार्टी कार्यकताओं का मनोबल बढ़ेगा। इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य गुरुवार को यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं के साथ इस शहर के विकास की दिशा में नई गति प्रदान करेगी।

बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार : पीएम मोदी

एजेंसी

मोतिहारी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार की एक दिवसीय यात्रा के क्रम में मोतिहारी पहुंचे। यहां उन्होंने गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की एनडीए सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इस दौरान लोगों को भरोसा देते हुए उन्होंने कहा, 'बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार'। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश को 7200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने आज जो विकास योजनाएं शुरू की हैं, उनसे बिहार के लोगों को बहुत फायदा होगा। कांग्रेस और राजद गरीबों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों के नाम

पर सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन ये लोग अपने परिवार के अलावा किसी और का सम्मान नहीं करते। हमें बिहार को इनसे बचाना है। नीतीश कुमार और भाजपा की टीम ने यहां कई सालों से कड़ी मेहनत की है विपक्षी दलों पर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग कभी बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें मिलकर बिहार के विकास को और गति देनी है। हमें संकल्प लेना है कि बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने एक नया नारा बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल देते हुए कहा कि पहले लालटेन के दौर वाला बिहार था, अब नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। हाल में बिहार सरकार की ओर से सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। पिछले डेढ़ महीने में ही 24 हजार से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद भेजी गई। ये सभी पैसे बैंक खातों में सीधे भेजे गए। केंद्र सरकार ने जनधन योजनाओं के तहत माताओं-बहनों के खाते खुलवाए हैं।

कविंदर गुप्ता ने लद्दाख के नए उपराज्यपाल पद की शपथ ली

एजेंसी

लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में शुक्रवार को कविंदर गुप्ता ने शपथ ली। राज निवास में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण पल्ली ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव पवन कोतवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से गुप्ता की नियुक्ति का वारंट पढ़ा। वह केंद्र शासित प्रदेश के तीसरे उपराज्यपाल हैं और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का स्थान लिया है, जिन्होंने 19 फरवरी, 2024 को केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का पदभार संभाला था। मिश्रा ने आरके माथुर का स्थान लिया था। जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किये जाने पर 2019 में उन्हें लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोमवार को कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने अतीत में सरकार और अपनी पार्टी दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों

पर कार्य किया है। वह 2018 में भाजपा-पीडीपी सरकार के दौरान 51 दिनों के लिए जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री रहे। जब भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, तो उन्होंने पद छोड़ दिया। जम्मू शहर के जानीपुर इलाके के रखने वाले 66 वर्षीय गुप्ता 2005 से 2010 तक लगातार तीन बार जम्मू के मेयर भी रह चुके हैं।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला:पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने किया गिरफ्तार

एजेंसी

रायपुर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार को छापेमारी की। फिलहाल चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा था। कुछ घंटे की गहन तलाशी के बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई। बता दें कि चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया गया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के समय कांग्रेस कार्यकर्ता भिलाई में पुलिस से भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ झड़प की और ईडी के वाहनों को रोकने की कोशिश की। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा में थे। ईडी की कार्रवाई के विरोध में विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की छापेमारी पर

कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की तरफ से पोस्ट में लिखा गया, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी भेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग को अपने पालतू की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष का जो भी नेता उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, उस पर छापे डलवा दिए जाते हैं। कांग्रेस ने इस पोस्ट में आगे लिखा, भूपेश बघेल शुक्रवार को विधानसभा में पेड़ काटने का मुद्दा उठाने वाले थे, उससे पहले ईडी भेज दी गई। लेकिन पीएम मोदी याद रखें, इन गीदड़ भभकियों से कांग्रेस और उसके नेता डरने वाले नहीं। हम और मजबूती से आपके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे।

नर्स निमिषा प्रिया मामला: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केस लड़ रही संस्था ने मांगी यमन जाने की इजाजत

एजेंसी

नई दिल्ली । यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले में 'सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल' नामक संगठन ने कोर्ट से अनुमति मांगी कि उन्हें यमन जाकर मृतक के परिवार वालों से बातचीत करने की इजाजत दी जाए। संगठन का मानना है कि मृतक के परिवार से बातचीत के जरिए निमिषा की सजा को माफ करने या कम करने की संभावना बन सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सरकार के पास ज्ञापन दीजिए। सरकार अपने हिसाब से इस पर फैसला लेगी। हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निमिषा की फांसी की सजा को फिलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने इसके लिए भारत सरकार का आभार जताया।वकील ने कहा कि अब उन्हें यमन जाकर मृतक के परिवार से बात करने की जरूरत है ताकि इस मामले में कोई सकारात्मक हल निकल सके। वहीं, भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमनी ने कोर्ट में कहा कि

सरकार नहीं चाहती कि इस मामले में कोई गलत कदम उठे, जिसका नकारात्मक परिणाम हो। सरकार का उद्देश्य निमिषा प्रिया को सुरक्षित भारत वापस लाना है। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में पूरी सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। बता दें, केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन में एक हत्याकांड में मौत की सजा सुनाई गई थी। नर्स निमिषा प्रिया 2008 से यमन में रह रही थीं। उन्होंने एक क्लीनिक शुरू किया था, लेकिन स्थानीय कानून का पालन करने के लिए यमन के नागरिक तलाल अब्दुल मेहदी को साझेदार बनाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलाल अब्दुल मेहदी ने बाद में निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया था। वह उनका पैसा हड़पने लगा और कथित तौर पर पासपोर्ट भी छीन लिया था। साल 2017 में पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश में निमिषा ने तलाल अब्दुल मेहदी को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन दिया।

राहुल गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट को बताया 'षड्यंत्र',कहा- सरकार 'मेरे जीजाजी को परेशान कर रही

एजेंसी

नई दिल्ली । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट को 'षड्यंत्र का हिस्सा' करार दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि उनके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को पिछले दस साल से यह सरकार (भाजपा सरकार) परेशान कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, 'मेरे जीजा रॉबर्ट वाड्रा को पिछले दस सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह चार्जशीट उसी षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं, क्योंकि वे दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने

आगे लिखा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि वे सभी किसी भी तरह के अत्याचार का साहसपूर्वक सामना करने में सक्षम हैं और वे हमेशा की तरह गरिमा के साथ इसे सहन करेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ रुपए की 43 संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच भी किया। ईडी की चार्जशीट के अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम जिले के शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपए में 'झूठे दस्तावेजों' के आधार पर 'धोखाधड़ी' से खरीदी थी। इसमें यह भी कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 'रसूख' का इस्तेमाल कर खरीदी गई जमीन पर व्यावसायिक लाइसेंस हासिल किया। यह जमीन खरीद सौदा फरवरी 2008 में हुआ था।

'वंदे भारत एक्सप्रेस का गैर वातानुकूलित संस्करण है अमृत भारत एक्सप्रेस

एजेंसी

पटना। दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) जयंत चौधरी ने 'अमृत भारत एक्सप्रेस' को 'वन्दे भारत एक्सप्रेस' का गैर वातानुकूलित संस्करण बताते कहा कि यह गरीबों और निम्न मध्य तीव्र गति से यात्रा की सुविधा मुहैया करायेगी। श्री चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस आम लोगों को कम समय में गंतव्य तक पहुंचाएगी। यह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का गैर वातानुकूलित संस्करण है, क्योंकि इसमें यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। हर बोगी में जगह-जगह सीसीटीवी लगाए गये हैं। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन का किराया अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों से थोड़ा ही अधिक है। गौरतलब है कि देशभर में अबतक सात अमृत भारत एक्सप्रेस संचालित हो रही हैं, जिनमें से चार ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आभासी माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तरह से बिहार में अब छह अमृत भारत एक्सप्रेस चलने लगी हैं।

आज जिन ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ उनका किराया निम्न प्रकार है। ट्रेन संख्या 15567 बापूधाम -आनंद विहार दिल्ली - 555 रुपये ,ट्रेन संख्या 22361 राजेन्द्र नगर, पटना-नयी दिल्ली - 560 रुपये, ट्रेन संख्या 15561 दरभंगा -गोमती नगर, लखनऊ - 415 रुपये, और ट्रेन संख्या 13435 मालदा टाउन - गोमती नगर, लखनऊ -540 रुपये।

ईडी की रडार पर आम आदमी पार्टी के नेता, मनी लॉन्ड्रिंग के तीन नए केस दर्ज

एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता एक बार फिर ईडी की रडार पर आ गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार के कार्यकाल के दौरान सामने आए तीन बड़े कथित घोटालों में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज कर लिए हैं। ये मामले अस्पताल निर्माण, सीसीटीवी परियोजना और शेल्टर होम से संबंधित हैं। ईडी ने इन मामलों में इन्फोर्समेंट केस इनफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है और जल्द ही आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को पूछताछ के लिए समन भेजे जा सकते हैं। पहला मामला 5,590 करोड़ रुपए के अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस घोटाले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। साल 2018-19 में दिल्ली सरकार द्वारा 24 अस्पताल परियोजनाएं मंजूर की गई थीं। इन आईसीयू अस्पतालों को छह महीने में तैयार करना था, लेकिन तीन साल बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। अब तक करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 50 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है। इसके अलावा, एलएनजेपी अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।

दूसरा मामला 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी घोटाले से जुड़ा है। 2019 में दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई थी। यह ठेका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल) को दिया गया, लेकिन परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई। भेल पर 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के माफ कर दिया गया था। तीसरा मामला 207 करोड़ की गड़बड़ी का डीयूएसआईबी शेल्टर होम घोटाले से जुड़ा है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (डीयूएसआईबी) से जुड़ी परियोजनाओं में भी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। आरोप है कि फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद के जरिये 207 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। लॉकडाउन के दौरान कागजों में दिखाया गया कि 250 करोड़ रुपए का शेल्टर होम का काम 'घोस्ट वर्कर्स' के नाम पर दर्शाया गया। इन कर्मचारियों की सैलरी नेताओं तक कमीशन के रूप में पहुंचाने का आरोप है।

नाटो प्रमुख, अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ धमकी पर भारत ने कहा- दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत ने अमेरिका और नाटो की रूस से कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी धमकियों का जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि इस मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं अपनाये जाने चाहिए। वर्तमान वैश्विक परिदृष्य में हमारी ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है तथा बाजार की स्थिति के अनुरुप भारत कदम उठाएगा। सैन्य संगठन नाटो के प्रमुख मार्क रूट की द्वितीयक प्रतिबंध की धमकी से जुड़े एक प्रश्न पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में कहा कि हमने उनके बयान को देखा है तथा घटनाक्रम पर नजर बनाये हुए हैं। हम दोहराना चाहते हैं कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसे देखते हुए भारत के निर्णय बाजार के माहौल और वैश्विक हालात पर निर्भर होंगे। उन्होंने इस मामले में दोहरे मानदंड अपनाने के प्रति सतर्क भी किया। मार्क रूट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के बाद भारत, चीन और ब्राजील पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जाने की धमकी दी थी। उन्होंने इन देशों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर दवाब बनाने के लिए कहा था। उन्होंने चेताया था कि ऐसा नहीं करने पर भारत, चीन और ब्राजील को प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे।

पिछले छह महीनों में 1563 भारतीयों को अमेरिका ने वापस भेजा

नई दिल्ली। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका में भारतीय नागरिकों की गिरफ़्तारी और निर्वासन से जुड़े मामलों में कानून का सम्मान करता है और भारतीयों से स्थानीय नियमों का पालन करने की अपेक्षा करता है। अमेरिका ने पिछले छह महीनों में 1563 भारतीयों को वापस भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में बताया कि 20 जनवरी से 15 जुलाई के बीच कुल 1563 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है। इनमें से अधिकांश को वाणिज्यिक उड़ानों से भारत भेजा गया। यह आंकड़ा अमेरिका के आव्रजन और कानून प्रवर्तन से संबंधित कार्रवाइयों का परिणाम है। एक अन्य मामले में अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में एक भारतीय नागरिक को बाल यौन सामग्री रखने के आरोप में गिरफ़्तार किए जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ा विषय है। भारतीय नागरिकों को स्थानीय कानूनों का पालन करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि विदेश जाने वाले भारतीयों को वहां के कानून, दिशा-निर्देश और नियमों का सम्मान करना चाहिए। वहीं एक अन्य घटना में एक भारतीय महिला पर्यटक को अमेरिका में दुकान से चोरी करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया। इस पर प्रवक्ता ने कहा कि हम हमेशा यह आग्रह करते हैं कि विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिक उस देश के कानूनों का पालन करें और भारत की सकारात्मक छवि बनाए रखें।

सोशल मीडिया वर्तमान में जनता से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम : जमाल सिद्दीक़ी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीक़ी ने कहा कि सोशल मीडिया वर्तमान में जनता से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मोदी सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण की योजनाएं, सरकार के ऐतिहासिक निर्णय तथा संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया सशक्त माध्यम है। जमाल सिद्दीक़ी भाजपा मुख्यालय में सोशल मीडिया पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, वरिष्ठ पत्रकार अफ़ज़ान शेख़, राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह प्रभारी जसवंत जैन एवं मरियम फारुकी उपस्थित रहे। कार्यशाला में देशभर से विभिन्न राज्यों के प्रदेश सोशल मीडिया व सह प्रभारी सम्मिलित हुए। सिद्दीक़ी ने कहा कि वर्तमान युग डिजिटल युग है जिसमें त्वरित जानकारी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साइबर योद्धा होने के नाते आप की जिम्मेदारी है ।

सीएआरए ने राज्यों को गोद लेने के सभी स्तरों पर परामर्श सहायता को मजबूत करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने सभी राज्यों के दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (एसएआरए) को गोद लेने के सभी स्तरों पर परामर्श सहायता तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसमें दत्तक ग्रहण प्रक्रिया से पूर्व, दत्तक ग्रहण के दौरान और दत्तक ग्रहण के बाद के सभी चरण शामिल हैं। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि ये निर्देश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 वर्ष 2021 में संशोधित) की धारा 70(1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जारी किए गए हैं और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

यमुना की सफाई से लेकर कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम जारी : रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अभी कामों की शुरूआत हुई है और विकास के बहुत सारे काम करने हैं। यमुना की सफाई से लेकर कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम जारी है। यह बातें मुख्यमंत्री ने घोंडा विधानसभा में मोहल्ला चौपाल का लोकार्पण करते हुए कही। इस मौके पर मंत्री कपिल मिश्रा, सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर, जिलाध्यक्ष यूके चौधरी समेत पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण को स्वच्छ करने की दिशा में लगातार काम जारी है। दिल्ली में विकास का एक भी काम नहीं छूटेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नए स्कूल और अस्पताल खोलने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। दिल्ली सरकार 24 घंटे और सातों

दिन काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली में उत्सव का माहौल है। दिल्ली सरकार के मंत्री विधायक और अधिकारी कांवड़ शिविरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। कांवड़ शिविरों को लेकर सभी तैयारियां समय पर पूरी करने ली गई है। उन्होंने कहा कि कांवड़ शिविर समितियों की आधी पेमेंट कर दी गई है और जरूरत के मुताबिक उनकी मदद की जाएगी। सभी कांवड़

> मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी में बुनियादी सुविधाओं और पर्यावरण को स्वच्छ करने की दिशा में लगातार काम जारी है।

शिविरों के निरीक्षण के दौरान व्यवस्था दुरुस्त पाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले टैंट माफिया कांवड़ यात्रा के पैसे खा लेते थे। इस बार दिल्ली सरकार ने एकल विंडो प्रणाली द्वारा 72 घंटे के अंदर कांवड़ समितियों को मंजूरी दी है। पिछले साल के 170 कांवड़ शिविरों के स्थान में इस बार 374 शिविर लगाए गए हैं। दिल्ली के मंत्री और विधायक कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं।

विदेश नीति को कमजोर कर रही है सरकार, संसद सत्र में व्यापक चर्चा हो : आनंद शर्मा

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार पर विदेश नीति को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के फैसलों की वजह से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रभाव लगातार घट रहा है, जो राष्ट्रीय चिंता का विषय है।उन्होंने इस मुद्दे पर आगामी मानसून सत्र में सरकार से चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा ने केंद्र सरकार पर विदेश नीति को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के फैसलों की वजह से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रभाव लगातार घट रहा है, जो राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने इस मुद्दे पर आगामी मानसून सत्र में सरकार से चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करता रहा है और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देशों से लेकर एशियाई देशों तक भारत की बात को सम्मानपूर्वक सुना जाता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रभाव हमारी आर्थिक या सैन्य ताकत की वजह से नहीं था, बल्कि हमारी नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण वाली विदेश नीति की वजह से था। शर्मा ने कहा कि 1950 के दशक में जब कोरिया संकट खड़ा हुआ था, तब भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने समाधान के लिए भारत की ओर देखा था। उन्होंने कहा कि आज यह एक प्रवृत्ति बन गई है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गहरा सम्मान था, की आलोचना की जाती है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत की आवाज को पूरी दुनिया ने गंभीरता से सुना क्योंकि हमारी विदेश नीति नैतिकता पर आधारित थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने विदेश नीति के मामले में राष्ट्रीय सहमति को कमजोर कर दिया है।

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और सिरसा ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर और अंडरपास कार्य का किया निरीक्षण किया

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संयुक्त रूप से शहरी विस्तार सड़क-II (यूईआर-2) और नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर और अंडरपास कार्य का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के बाद मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सभी कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर यहां हुए काम की कमियों की जांच की जा रही है। हम इसे दोबारा अध्ययन करेंगे और जो भी कमियां या गैप हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को तात्कालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और व्यावहारिक समाधान चाहिए और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह परियोजना नजफगढ़, द्वारका, रोहिणी और दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाइवे (शिव मूर्ति चौराहा) जैसे महत्त्वपूर्ण इलाकों को जोड़ने वाले इस चौराहे पर निर्बाध यातायात

सुनिश्चित करेगी और वैकल्पिक मार्गों पर मौजूद दबाव को भी कम करेगी। इस मौके पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदूषण को नियंत्रित करना है, जो भारी ट्रैफिक के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करने के तरीके खोजने पर काम कर रहे हैं। ऐसे परियोजना सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, बल्कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधारने में भी अहम भूमिका निभाएंगे।

डीटीसी में मुफ्त यात्रा के लिए दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा 'पिंक कार्ड' : रेखा गुप्ता

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिंक टिकट के स्थान पर अब सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए पिंक कार्ड देने की तैयारी की गयी है। इससे बार-बार टिकट लेने का झंझट खत्म हो जाएगा और सरकार सिर्फ पिंक कार्ड के मुताबिक ही दिल्ली परिवहन निगम को पैसा देगी।

मुख्यमंत्री नंद नगरी स्थित दिल्ली परिवहन निगम डिपो में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखने के बाद समारोह को संबोधित कर रही थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आधुनिक केंद्र हर वर्ष लगभग 72,000 वाहनों की फिटनेस जांच की क्षमता रखता है। यहां शून्य मानवीय हस्तक्षेप के साथ वाहन परीक्षण होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और तकनीक-आधारित बनेगी। यह केंद्र न केवल सड़क सुरक्षा को मजबूती देगा, बल्कि दिल्ली में हरित, कुशल और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को

भी बढ़ावा देगा उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए सरकार नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है। इस मौके पर परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि 2019 में आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने डीटीसी में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए पिंक टिकट योजना शुरू की थी।

मुख्यमंत्री ने की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात, दिल्ली को मिलेगी 600 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय में हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने दिल्ली की विकास यात्रा, मौजूदा योजनाओं की प्रगति और भविष्य की आवश्यकताओं से उन्हें अवगत कराया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को इस महीने के अंत तक 600 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि के लिए वह शीघ्र की प्रस्ताव वित्त मंत्रालय भेज रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से

मिलने वाली इस धनराशि का प्रयोग दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए किया जाएगा। इस राशि का उपयोग दिल्ली में यातायात प्रबंधन, जल निकासी, हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन आदि योजनाओं में भी किया होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगात्मक रवैये के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों का प्रत्यक्ष लाभ महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि एसएएससीआई योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और दिल्ली को एक विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय व दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि यह मुलाकात न केवल दिल्ली के विकास को गति देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही, बल्कि यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोगात्मक संघवाद की भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है।

हिमंता बिस्वा सरमा पर राहुल गांधी की टिप्पणी को भाजपा ने आपत्तिजनक बताया

एजेंसी

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को जेल भेजने की राहुल गांधी की टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी ने आपत्तिजनक बताया है। भाजपा ने कहा कि खुद जमानत पर बाहर रहने वाले परिवार द्वारा किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजने की बात करना विडंबनापूर्ण है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सैयद जफर इस्लाम ने गुरुवार को केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से कहा कि इस तरह के बयानों से राहुल गांधी असम में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत कर असम के मुख्यमंत्री बने हैं, न कि राहुल गांधी के रहमोकरम पर। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सहित कांग्रेस शासित हर राज्य में राहुल मॉडल फ्लॉप हो चुका है। जबकि भाजपा की हर राज्य सरकार का सुशासन मॉडल आज पूरे देश की जनता देख रही है और इसीलिए भाजपा को विजयी बना रही है। बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) मामले में विपक्ष के बयान को लेकर डॉ. इस्लाम ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस समेत विपक्षी नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के नेता भ्रम की राजनीति कर बिहार में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉ. इस्लाम ने कहा कि बिहार की जनता जंगलराज स्थापित करने वालों को दोबारा मौका न देने का पूरा मन बना चुकी है। इसीलिए बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सुशासन सरकार बनने जा रही है।

दिल्ली विधानसभा 21 जुलाई से तीन दिवसीय नेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेगी आयोजन

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा सभी विधायकों के लिए तीन दिवसीय नेशनल ई विधान लोकेशन (नेवा) प्रशिक्षण कार्यक्रम का 21 से 23 जुलाई तक आयोजन कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा विकसित किए जा रहे विशेष प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। विधानसभा द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी जानकारी दी गई।विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि नेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को आगामी मानसून सत्र के लिए ई-विधान पोर्टल प्लेटफार्म के उपकरणों और कार्यप्रणालियों से परिचित कराना है। तीन दिनों के इस प्रशिक्षण के दौरान, विधायकों को पोर्टल दस्तावेजों की पहुंच, विधायी कार्य की रीयल-टाइम ट्रैकिंग, प्रश्न और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सहित अन्य पोर्टल कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो एक आधुनिक और कुशल विधानसभा संचालन के

लिए आवश्यक हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस नए नेवा प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 18 से 20 कंप्यूटर लगाए जाएंगे जिससे कि विधायकों को प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक (हैंड्स-ऑन) अनुभव प्रदान किया जा सके। इस प्रशिक्षण में संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ विधायकों को नेवा प्लेटफॉर्म की विशेषताओं और कार्यप्रणाली से अवगत कराएंगे। ये विशेषज्ञ विधायकों को आधुनिक विधायी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक डिजिटल उपकरणों और कार्यप्रणाली को समझाने के लिए प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

उपराष्ट्रपति ने यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क का दौरा किया, बोले- देश ने की एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति

एजेंसी

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण के सराय काले खां स्थित यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क का दौरा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी का यहां स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने पिछले एक दशक में अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस दौरान देश दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का तेजी से विकास हुआ और देशवासियों को सड़कें, बिजली, गैस, शौचालय, इंटरनेट, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं आसानी से मिल रही है। धनखड़ ने उपराज्यपाल के किए कामों को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि पर्यावरण को लेकर दिल्ली में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने दिल्ली वालों से यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए भी कहा। यमुना वाटिका को दिल्ली का सबसे बड़ा और विशिष्ट हरित क्षेत्र माना जा रहा है।

शैक्षणिक संस्थाओं को भयभीत करने वाले ब्यान के लिए माफी मांगें अरविंद केजरीवाल- भाजपा

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शैक्षणिक संस्थाओं को मिली धमकी मामले पर आम आदमी पार्टी (आआपा) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयानों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं को भयभीत करने वाले ब्यान के लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए ।

वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक बयान में कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को मिली धमकी को दिल्ली पुलिस पूरी गम्भीरता से लेती रही है। फौरी सुरक्षा जांच के साथ त्वरित साइबर जांच कर धमकी देने वाले तक को सामने लाती है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि स्कूल में छुट्टी के इच्छुक एक स्कूली छात्र ने ही फर्जी धमकी देकर स्कूल आदि को फर्जी ईमेल भेजने का कुकृत्य किया। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए प्रयोग कर रहे है और ब्यानबाजी कर दिल्ली में छात्रों एवं अभिभावकों में तनाव

पैदा करने की कोशिश कर रहे है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनवरी 2025 में भी आआपा ने स्कूलों को मिली धमकी का राजनीतिक दुरूपयोग करने का प्रयास किया था। जिसमें एक 12 वर्षीय छात्र दोषी निकला था। उन्होंने कहा कि उस छात्र के पिता के तार आआपा की नेता आतिशी मार्लेना के माता-पिता की एन.जी.ओ. से जुड़े निकले थे। सचदेवा ने कहा कि आज का छात्र साइबर प्रयोग में काफी सक्रिय है सोशल मीडिया पर सक्रिय है और स्कूल पाठ्यक्रम में भी ईमेल का प्रयोग हो रहा है।

ऐसे में उनके पास कम उम्र से ईमेल आदि के प्रयोग की छूट रहती है और एक कमजोर क्षण में कोई बच्चा उस छूट का दुरुपयोग कर जाता है। उन्होंने कहा कि इश बार भी शायद वैसे ही मामले सामने आए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली वाले आशा करते हैं कि भविष्य में स्कूल से हवाई याण कम्पनी तक किसी को भी धमकी मिलने पर अरविंद केजरीवाल एवं उनकी पार्टी ओछी राजनीतिक ब्यानबाजी से बचते हुए सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास रखेंगे।

माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो अभियान पूरा करके लौटे पर्वतारोही, रक्षा सचिव ने किया स्वागत

एजेंसी

नई दिल्ली। माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो अभियान पूरा करके पर्वतारोहियों का दल दिल्ली लौट आया, जहां साउथ ब्लॉक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पर्वतारोहियों का स्वागत किया। माउंट एवरेस्ट अभियान के दल ने खुम्बू घाटी से होते हुए 23 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसी तरह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटीमाउंट किलिमंजारो पर 8 अगस्त, 2024 को अभियान दल ने सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो के पर्वतारोहण अभियानों का दल दिल्ली लौटा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने साउथ ब्लॉक में औपचारिक रूप से स्वागत किया। माउंट एवरेस्ट का यह अभियान उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से दार्जिलिंग के हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान और जम्मू और कश्मीर के जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान के सहयोग से किया गया था। ?इसी तरह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का अभियान हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान ने आयोजित किया था। इस अभियान में दिव्यांग उदय कुमार भी शामिल जिनका घुटने के नीचे हिस्सा 91 प्रतिशत तक प्रभावित था। रक्षा सचिव ने अपने संबोधन में दोनों दलों के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और साहस की सराहना करते हुए इस बात पर बल दिया कि ये मिशन केवल चोटियों पर चढ़ाई करने के संदर्भ में नहीं थे, बल्कि साहसिक खेलों में भारत की पर्वतारोहण उत्कृष्टता और नेतृत्व को प्रदर्शित करने से भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इन दलों ने देश और दुनिया भर के युवा पर्वतारोहियों को प्रेरित करने के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के चारों संस्थानों और राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान (निमास) को इस दृष्टिकोण का ज्वलंत उदाहरण बताया।माउंट एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया ने किया।

संपादक की कलम से

एचआईवी संक्रमण से मुक्ति की जंग अब भी अधूरी

आज जब दुनिया स्वास्थ्य सुरक्षा, जैविक आपदाओं और महामारी नियंत्रण के नए अध्यायों से गुजर रही है। आज यदि एक प्रभावी एड्स वैक्सीन विकसित होती है और भारत तक उसकी पहुँच सुनिश्चित होती है, तो इसके बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। भारत में लगभग चौबीस लाख लोग एचआईवी से संक्रमित हैं, जिनमें से अनेक ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से हैं। वैक्सीन उपलब्ध होने से संक्रमण दर में नाटकीय गिरावट संभव है, जिससे स्वास्थ्य तंत्र पर बोझ घटेगा, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी। विशेषकर वाणिज्यिक यौनकर्मियों, ट्रांसजेंडर समुदाय, समलैंगिक पुरुषों और नशे की लत के शिकार व्यक्तियों जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों को दीर्घकालिक संरक्षण प्राप्त होगी। यह वैक्सीन केवल स्वास्थ्य संकट का समाधान नहीं होगी, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगी।

कोविड महामारी के अनुभव ने यह सिखाया कि जब विज्ञान, सरकार और समाज एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। मात्र एक वर्ष में कोविड की वैक्सीन बन गई, जबकि एचआईवी जैसी महामारी को चार दशक बीत जाने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी टीका नहीं मिल सका है। यह तुलना यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एचआईवी से जुड़ी वैक्सीन अनुसंधान को वह राजनीतिक इच्छाशक्ति, आर्थिक संसाधन और जन समर्थन मिला जो कोविड के मामले में मिला था?

ग्रामीण क्षेत्रों, अशिक्षित जनसमूह और ट्रांसजेंडर समुदाय जैसे संवेदनशील वर्ग आज भी भेदभाव, कुप्रचार और अज्ञानता का शिकार हैं। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे सामान्य बीमारियां भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। यदि समय रहते इसका पता न चले और इलाज न हो, तो एड्स होने पर जीवन की संभावना कम हो जाती है। साथ ही, यह संक्रमण असावधान यौन संबंध, संक्रमित सुई का उपयोग, और रक्त संचरण के जरिए तेजी से फैल सकता है। इसलिए एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, और इसके प्रसार को रोकने के लिए सतत जागरूकता, सुरक्षित व्यवहार, और अनुसंधान की जरूरत है । आज के डिजिटल युग में जहां सूचना की पहुंच आसान हो गई है, वहीं एड्स से जुड़ी भ्रांतियां और कलंक अब भी मिट नहीं सके हैं। यही वह मानसिक दीवारें हैं जिन्हें तोड़ना, एक प्रभावी वैक्सीन की खोज से भी ज्यादा जरूरी हो चला है। आज के युवा जागरूक, तकनीकी रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से अधिक संवेदनशील हैं। उन्हें स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया मंचों पर एचआईवी के बारे में खुलकर संवाद करना चाहिए। सुरक्षित यौन व्यवहार, नियमित जांच और संक्रमितों के साथ करुणामय व्यवहार को सामान्य बनाना होगा। यही वह सामाजिक आधार होगा जिस पर कोई भी वैक्सीन कार्यक्रम सफल हो सकता है ।

आज के परिप्रेक्ष्य में, जब भारत वैश्विक जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, यह बेहद आवश्यक है कि सरकार और नीति-निमार्ता एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जनस्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाना होगा ताकि बेहतर परीक्षण, उपचार और रोकथाम की सुविधाएं हर स्तर पर उपलब्ध हो सकें। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित वर्गों तक स्वास्थ्य शिक्षा और संसाधनों की सहज पहुँच सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे भी समय पर जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकें। साथ ही, एड्स से जुड़े सामाजिक कलंक और भेदभाव को मिटाने के लिए व्यापक राष्ट्रीय जन जागरण अभियान चलाना होगा, जिससे समाज में समावेशन और संवेदनशीलता बढ़े तथा संक्रमितों को सम्मान और सहयोग मिल सके।आम आदमी से अपेक्षा की जाती है। कि वह एड्स से जुड़े मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाए। वे सही जानकारी प्राप्त करके अपने परिवार और समाज में जागरूकता फैलाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाएं और समय-समय पर एचआईवी परीक्षण करवाएं। साथ ही, एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और सम्मान बनाए रखें, उनके साथ बीच सही संदेश फैलाकर वे इस बीमारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

यही सहयोग और समझदारी ही एड्स मुक्त समाज के निर्माण की नींव रख सकती है। आज के युग में, जब विज्ञान ने चमत्कार करने की क्षमता दिखाई है, तब यह और जरूरी हो गया है कि हम एचआईवी वैक्सीन पर जन-ध्यान केंद्रित करें।यदि हम आज निर्णय लें कि भविष्य एड्स-मुक्त होना चाहिए, तो विज्ञान, समाज और शासन झ तीनों मिलकर वह भविष्य रच सकते हैं।

कांग्रेस के विरोध के बाद भी मोदी के खास

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सख्त रुख को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से रखने के लिए एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। इस रणनीति के तहत भारत सरकार ने एक के बाद एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित कर दुनिया के उन देशों की यात्रा की योजना बनाई है जो या तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं या फिर भारत के रणनीतिक सहयोगी माने जाते हैं। इन प्रतिनिधिमंडलों का उद्देश्य न केवल भारत के पक्ष को वैश्विक समुदाय के सामने स्पष्ट करना है, बल्कि यह दिखाना भी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह एकजुट है। लेकिन इस राष्ट्रहित की कवायद के बीच एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के भीतर बहस को जन्म दे दिया है बल्कि केंद्र और विपक्ष के रिश्तों में भी खटास बढ़ा दी है। विवाद की जड़ में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम है जिन्हें केंद्र सरकार ने बिना कांग्रेस नेतृत्व की सिफारिश के एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर लिया। जबकि कांग्रेस का दावा है कि उसने अपनी तरफ से चार वरिष्ठ सांसदों के नाम सरकार को भेजे थे, जिनमें से किसी को भी नहीं चुना गया। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सरकार ने अपनी मनमर्जी से शशि थरूर को चुना और उन्हें प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंप दिया। वहीं, केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस से कोई औपचारिक नाम नहीं मांगे गए थे, बल्कि जो जानकारी दी गई थी, वह केवल सूचनात्मक थी, कोई आग्रह नहीं। कांग्रेस इस सफाई से संतुष्ट नहीं है और उसका मानना है कि सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस को दरकिनार किया और शशि थरूर को शामिल कर सियासी संदेश देने की कोशिश की।

यह पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर की कांग्रेस नेतृत्व से टकराव की स्थिति सामने आई है। इससे पहले भी वे विदेश राज्य मंत्री रहते हुए ह्यकैटल क्लासह्न जैसे ट्वीट की वजह से विवादों में आए और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़े होने के बाद से तो पार्टी के भीतर उन्हें शक की नजर से देखा जाने लगा। लेकिन इन सबके बावजूद शशि थरूर की एक अलग पहचान है एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभवी राजनयिक की, जो संयुक्त राष्ट्र में 30 साल से ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनकी वाक्पटुता, कूटनीतिक समझ और वैश्विक मंचों पर प्रभावशाली उपस्थिति ने उन्हें न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी विशिष्ट पहचान दिलाई है। शशि थरूर ने खुद को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किए जाने पर खुशी और गर्व का इजहार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि वे भारत सरकार के इस आमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहे हैं और जब भी राष्ट्रीय हित की बात होगी, वे पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने किसी तरह की पार्टी अनुमति की आवश्यकता नहीं समझी, जो कांग्रेस नेताओं को खटक गया। पार्टी नेतृत्व का यह मानना है कि थरूर को पहले नेतृत्व से राय लेनी चाहिए थी, लेकिन शायद थरूर को खुद ही इस बात की आशंका थी कि यदि वे अनुमति मांगते तो उन्हें मना कर दिया जाता। ऐसे में उन्होंने खुद ही निर्णय लेना उचित समझा, खासकर तब जब उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव मिला। शशि थरूर की इस भूमिका से न केवल बीजेपी को लाभ मिल रहा है बल्कि खुद थरूर की राजनीतिक हैसियत भी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में विदेश नीति पर बोलते हुए कांग्रेस पर हमला करते हैं, तब वे विशेष रूप से यह कहते हैं कि शशि थरूर इस दायरे से बाहर हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि कांग्रेस को यह चुभेगा। वहीं, बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी थरूर की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी विदेश नीति की समझ और संयुक्त राष्ट्र में उनके अनुभव से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस ने उन्हें क्यों नहीं चुना? क्या यह राहुल गांधी की असुरक्षा की भावना है? यह सवाल बीजेपी के माध्यम से आम जनमानस के बीच भी फेंका गया है, जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस की तरफ से जिन चार सांसदों के नाम सुझाए गए थे उनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ. सैयद नसीर हुसैन और राजा ब्रार शामिल थे। आनंद शर्मा पूर्व विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। वहीं, राजा ब्रार और नसीर हुसैन को लेकर भी राजनीतिक विवाद जुड़ा रहा है। राजा ब्रार पर खालिस्तानी समर्थक गायकों के समर्थन का आरोप लगा है और नसीर हुसैन की एक रैली में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगने की घटना भी विवाद का कारण बनी थी। ऐसे में शशि थरूर का नाम इनमें से अधिक उपयुक्त और अंतरराष्ट्रीय छवि वाला नजर आता है। दरअसल, कांग्रेस को इस बात की तकलीफ है कि एक ऐसा नेता जो पार्टी के भीतर लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है, आज राष्ट्रीय मंच पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित किया जा रहा है। यह बात कांग्रेस के नेतृत्व को असहज कर रही है।

हालांकि पार्टी के कुछ नेता यह मानते हैं कि थरूर की राय और सोच भले ही अलग हो, लेकिन पार्टी को उन्हें अपने साथ बनाए रखना चाहिए क्योंकि उनका अंतरराष्ट्रीय अनुभव और बौद्धिक क्षमता कांग्रेस के लिए ताकत बन सकती है। कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में हालांकि कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि थरूर ने पार्टी की लक्ष्मण रेखा पार कर ली है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। एक ओर कांग्रेस थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, तो दूसरी ओर वह उन्हें खुला समर्थन भी नहीं दे पा रही है। यह दुविधा कांग्रेस नेतृत्व के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और सत्ता संरचना की अस्थिरता को दशार्ती है। शशि थरूर एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी लाइन से इतर राय रखने की हिम्मत करते हैं और अपनी बातों को खुले मंच पर रखते हैं। यही बात उन्हें विशिष्ट बनाती है और शायद यही बात कांग्रेस नेतृत्व को चुभती भी है। इस पूरे प्रकरण का एक और पहलू यह है कि थरूर को केरल में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी केंद्र सरकार ने आगे किया है। केरल में कांग्रेस के लिए हर सीट महत्वपूर्ण है, और वायनाड से राहुल गांधी के सांसद होने के कारण इस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर पार्टी विशेष नजर रखती है। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और उनकी लोकप्रियता के चलते बीजेपी को लगता है कि उनके माध्यम से केरल में एक वैकल्पिक नैरेटिव खड़ा किया जा सकता है।

यदि थरूर को कांग्रेस में उचित सम्मान और भूमिका नहीं दी गई तो यह संभावना बन सकती है कि वे किसी भी समय पार्टी छोड़ दें या कम से कम एक स्वतंत्र रुख अख्तियार कर लें, जो कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित होगा। शशि थरूर के पास इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन को नई दिशा देने का पूरा अवसर है। वो न तो कांग्रेस के लिए पूरी तरह विश्वसनीय रहे हैं, न ही बीजेपी के लिए आज्ञाकारी। लेकिन यही स्थिति उन्हें खास बनाती है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि थरूर जैसे नेता पार्टी की विविधता और बौद्धिक गहराई का प्रतीक हैं। यदि उन्हें दरकिनार किया जाता है तो इससे न केवल पार्टी की छवि को नुकसान होगा, बल्कि ऐसे नेताओं के बीच भी निराशा बढ़ेगी जो विचार और विवेक के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं।

अब देखना यह है कि कांग्रेस इस चुनौती से कैसे निपटती है। क्या वह शशि थरूर को उनके हाल पर छोड़ देगी, या फिर उन्हें पार्टी के भीतर सम्मानजनक भूमिका देकर संतुलन साधेगी? केंद्र सरकार की रणनीति तो साफ है विपक्ष के प्रभावशाली नेताओं को अलग-थलग करना, उन्हें राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठा देना और इससे विपक्ष के भीतर मतभेद को और गहरा करना। कांग्रेस यदि समय रहते नहीं चेती, तो यह मामला सिर्फ शशि थरूर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष और टकराव को और गहरा कर देगा। राजनीति में प्रतीकात्मक घटनाओं का बड़ा महत्व होता है, और शशि थरूर की यह नियुक्ति भी आने वाले समय में भारतीय राजनीति के समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।

आरक्षण: पीढ़ीगत विशेषाधिकार या वास्तविक न्याय?

डॉ सत्यवान सौरभ

भारत में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय रहा है। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और ऐतिहासिक उत्पीड़न के निवारण का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, आरक्षण की अवधारणा अपने मूल उद्देश्यों से भटकती प्रतीत होती है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई का बयान इस बहस को एक नई दिशा में ले जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करने का निर्णय संसद को करना चाहिए। उनका यह कथन कई सवाल खड़े करता है झ क्या आरक्षण का वास्तविक लाभ उस वर्ग तक पहुंच रहा है जिसके लिए यह बनाया गया था? क्या यह व्यवस्था अब सुधार और पुनर्विचार की मांग करती है?

आरक्षण का मूल उद्देश्य

आरक्षण का आरंभ भारतीय समाज में व्याप्त गहरी सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने और सदियों से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से हुआ था। यह एक ऐसा साधन था जिससे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। संविधान निमार्ता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने आरक्षण को एक अस्थायी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया था, ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को न्याय और अवसर मिल सके। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहाँ जातीय भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न का कोई स्थान न हो। यह केवल सरकारी नौकरियों और शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि एक समग्र सामाजिक सुधार की दिशा में एक साहसिक कदम था। लेकिन, धीरे-धीरे यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए एक पीढ़ीगत विशेषाधिकार बनती जा रही है जो पहले ही सशक्त हो चुके हैं। न्यायमूर्ति गवई का यह कहना कि जब एक व्यक्ति क्अर या क्कर बन जाता है, तो उसके बच्चे उसी समाज की कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं, एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर इशारा करता है।

राष्ट्र के सम्मान को आहत करता विजय का बयान

मध्यप्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह का बयान देश की राष्ट्रीय अस्मिता को कलंकित करने वाला है, राष्ट्र के सम्मान को आहत करने वाला है, जिस भारतीय सेना की कर्नल सौफिया कुरैशी ने आपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्र का मस्तक ऊँचा उठाया हो, ऐसे सैन्य अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक मंच से अपने बयान मे उन्हें आंतकवादियों की बहन बताने का जो घृणित पाप किया है, वह पुरे देश को आहत कर गया। जब राष्ट्र आपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान मे जाकर आंतकवादियों की पनाहगाहों को नेस्तनाबूत करने का जश्न मना रहा था, राष्ट्र की बेटी कर्नल सौफिया कुरैशी ने जब दुनियाँ को भारत के सधे कदमों से आंतकवाद के खिलाफ सैन्य कार्यवाही से अवगत कराया तब सारे भारत का मस्तक गर्व से ऊँचा उठ गया था, सौफिया व्योमिका की जुगलबंदी आपरेशन सिंदूर के घटनाक्रमों से देश दुनियाँ को अवगत करा रहे थे, भारत इस दौरान अपनी राष्ट्रीय एकता के दर्शन से भी दुनियाँ को वाकिफ करा रहा था। भारत की इस बेटी कर्नल सौफिया के विरुद्ध एमपी सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री, 8 बार के विधायक विजय शाह का बयान शर्मसार करने वाला है, इस मंत्री ने अपने भाषण मे कर्नल सौफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की है वह देश को नागवार गुजरी सोशल मिडिया पर मंत्री के इस बयान की कढ़ी आलोचना देखने को मिली। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा विजय शाह की मंत्री पद से बर्खास्तगी एवं एफआईआर तुरंत होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पुरे देश को लज्जित किया है। प्रदेश मे कांग्रेस संगठन ने भी मुखर विरोध दर्ज कराया तथा एफआईआर और बर्खास्तगी की मांग करते हुए शाह के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया।

मप्र हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मंत्री विजय शाह के विरुद्ध सख्त टिप्पणी करते हुए एफआईआर दर्ज कराने को लेकर डीजीपी को निर्देशित किया, बुधवार रात एमपी के मानपुर थाने मे विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गयी। एफआईआर के बाद प्रदेश ही नहीं सम्पूर्ण देश से एक स्वर मे मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की जा रही है, बदजुबान मंत्री सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणीयों के उपरांत भी मंत्री अपने पद पर बने हुए है। प्रदेश सरकार भी सख्त रुख नहीं अपना पा रही है।

अपनी बदजुबानी के लिये कुख्यात मंत्री विजय शाह ने सावजनिक मंच से जो कहा वह एक संवैधानिक पद पर बैठे प्रदेश के मंत्री को शोभा नहीं देता। उनकी टिप्पणी सेना और राष्ट्र के मनोबल को कमजोर करने वाली है, ऐसे समय जब भारत देश आंतकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ रहा हो तब प्रदेश के किसी मंत्री का उक्त बयान असहनीय, पीड़ादायी और राष्ट्रविरोधी माना जाना चाहिए। होना तो यह चाहिए था की मंत्री के बयान के तुरंत बाद प्रदेश की सरकार के मुखिया ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना चाहिए थी, उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए था। किंतु प्रदेश की सरकार ने रिपोर्ट दर्ज कराने का साहस नहीं दिखाकर जनभावना का अपमान किया है। जनभावना को समझकर राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक प्रावधानों की रक्षार्थ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वतः सज्ञान लेकर प्रदेश के डीजीपी को तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराने का सख्त निर्देश दिया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी एमपी के उच्च न्यायालय के आदेश को उचित मानते हुए मंत्री को फटकार लगाई। मप्र उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन मे मानपुर थाने मे एफआईआर दर्ज की गयी। एमपी हाई कोर्ट का उक्त आदेश सम्पूर्ण भारतवासियों के मन मे न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ाने वाला प्रतीत हो रहा है। आपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यप्रदेश के नागरिक इसलिए भी गौरव से भरे हुए थे, जब उन्हें यह सूचना मिली की आपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा आंतकवादियों की शरणस्थली पाकिस्तान मे जाकर आंतक के ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। भारत की सैन्य कार्यवाहीयों को दुनियाँ के समक्ष रखने की जवाबदेही निभाने वाली कर्नल सौफिया की प्रारम्भिक शिक्षा एमपी के छतरपुर के नौगाँव मे अपने चाचा के यहां हुई है।

सीमित युद्ध से भारत को सीखने होंगे कई सबक

आज समझदारी इसी में है कि युद्ध के कोहरे के बीच क्या सही या गलत हुआ, इस बाबत सभी बाहरी दावों और प्रतिदावों को त्याग दिया जाए। समाचार मीडिया एंकरों और स्व-घोषित अति-राष्ट्रवादियों ने कई (ज्यादातर झूठे) दावे कर गड़बड़ कर दी है। सरकार समर्थक मीडिया ने अपने आकाओं की सेवा में काल्पनिक दावों की ऐसी झड़ी लगा दी जिससे सरकार शर्मिंदा हो सकती है और मीडिया ने खुद को बेकार साबित कर दिया है।

पहलगाम में आतंकवादी हत्याओं की निंदा करने और रक्षा बलों को सलाम करने में सारा देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा है। इस घटना के कारण पाकिस्तान पर भारत ने पांच दशकों में इतना सघन हमला किया। भारत की इस कार्रवाई के लिए व्यापक समर्थन आतंकवादियों को खोजने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के राष्ट्रीय संकल्प को दशार्ता है। फिर भी, यह संकल्प आत्म-प्रशंसा के शोर के एक प्रतिध्वनि कक्ष में उतरने का जोखिम उठाता है जो राष्ट्र को उस गहन विश्लेषण से रोक सकता है।

इस संघर्ष में हालांकि कुछ भारतीय उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया लेकिन इस स्तर पर यह तर्क देना मुश्किल है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सफलता थी। भले ही ऑपरेशन में सीमित सफलता मिली है लेकिन इससे मिले सबक असीमित हैं। हमारे पास डेटा की एक खदान है जिसमें राजनीतिक ग्राउंड वर्क, राजनयिक जुड़ाव और योजना, रणनीति या परिचालन मुद्दों के विचारों से लेकर उच्च तकनीक वाले सैन्य हार्डवेयर व अत्याधुनिक प्लेटफार्मों के प्रदर्शन पर समृद्ध युद्ध क्षेत्र डेटा तक शामिल हैं।

अगली लड़ाई उन लोगों द्वारा जीती जाएगी जो सैन्य मोर्चे पर इन सीखों पर अच्छी तरह से अमल कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा सबक विशेष रूप से राजनीतिक मोर्चे पर होगा जहां युद्ध पर बड़े निर्णय लिए जाते हैं। सीखना हमेशा आसान नहीं होता है। उच्चतम राजनीतिक स्तर पर, यह उस रणनीति को चुनौती देता है जिसने हमें मर्दानगी की बातें और युद्ध के नारे दिए, जिसमें चुनावी रैली भी शामिल है, लेकिन युद्ध के समय अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत के कम सबूत मिले. साथ ही, विनम्रता, ईमानदारी और जिज्ञासा की भावना के साथ कठिन सवालों को प्रोत्साहित करने की इच्छा भी होनी चाहिए, जिनमें से कोई भी आत्म-प्रशंसा से मदद नहीं करता है जो गहन जांच को बंद कर देता है।

साथ ही अगर हमें इस मुद्दे पर राष्ट्रीय एकता का पूरा लाभ उठाना है तो विपक्ष पर चुनावी शैली के हमलों के बजाय राजनीतिक दलों को अधिक विश्वास-निर्माण करने वाले कदमों के साथ एक साथ लाना होगा।

पहलगाम आतंकी हत्याओं के ठीक दो दिन बाद 24 अप्रैल को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जब लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं सहित सभी राजनीतिक नेता मौजूद थे, उसमें प्रधानमंत्री के शामिल न होने के फैसले से विश्वास बहाली में कोई मदद नहीं मिली। वह गलत निर्णय पुरानी ढर्रे की नीतियों के आधार पर लिया गया था। विभिन्न देशों की राजधानियों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का सरकार का निर्णय अलग है। यह दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देता है लेकिन कांग्रेस द्वारा नामित नहीं किए गए शशि थरूर के सूची में शामिल होने पर पैदा हुआ विवाद- एक अनावश्यक चुभन- हमें बताता है कि पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। हम उन पाठों पर वापस आ गए जो सीखे नहीं गए हैं। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि भाजपा गेम खेल रही है। यह एक ऐसे मुद्दे पर कमजोर भरोसे और खराब राजनीतिक संबंधों में उतरता है जो गहरी राजनीतिक एकता की मांग करता है।

जानकारियां जिस तरह से अर्थहीन हो गई है उससे कुछ सबक मिलते हैं। आज समझदारी इसी में है कि युद्ध के कोहरे के बीच क्या सही या गलत हुआ, इस बाबत सभी बाहरी दावों और प्रतिदावों को त्याग दिया जाए। समाचार मीडिया एंकरों और स्व-घोषित अति-राष्ट्रवादियों ने कई (ज्यादातर झूठे) दावे कर गड़बड़ कर दी है। सरकार समर्थक मीडिया ने अपने आकाओं की सेवा में काल्पनिक दावों की ऐसी झड़ी लगा दी जिससे सरकार शर्मिंदा हो सकती है और मीडिया ने खुद को बेकार साबित कर दिया है। यह ऐसे दोस्तों का मामला है जो दुश्मनों से भी बदतर काम कर रहे हैं। मीडिया तब सही तरीके से काम करता है जब सभी प्रकार के विचारों को फलने-फूलने की अनुमति दी जाती है। इसका उदाहरण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॅन हैं जहां पर ग्राहक समीक्षाओं का समग्र मूल्यांकन कर नकारात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकाशित की जाती है। एकतरफा विचारों से चिह्नित एक पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उस पक्ष के लिए बुरा है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ये प्राथमिक सबक हैं जिन्हें फिर से सीखने की आवश्यकता हो सकती है।

युद्ध अंतिम उपाय है। यह भारत कह चुका है और इसे वास्तव में प्रधानमंत्री ने अतीत में व्यक्त किया है। 2022 में कारगिल में प्रधानमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था- 'भारत ने हमेशा युद्ध को अंतिम उपाय के रूप में देखा है, लेकिन राष्ट्र पर बुरी नजर डालने वाले किसी भी व्यक्ति को करारा जवाब देने की ताकत और रणनीति सशस्त्र बलों के पास है'। तो भी जब इस अंतिम उपाय का प्रयोग किया जाता है तो ब्रह्मास्त्र अपनी शक्ति खो सकता है। इसका उसी तरह से फिर से उपयोग या संचालन नहीं किया जा सकता। कम कार्रवाई को हल्के में लिया जाएगा, मजबूत कार्रवाई से अस्वीकार्य स्तर के जोखिम के साथ तेजी से वृद्धि का जोखिम होगा। डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पहले जल्दबाजी में घोषित किए गए संघर्ष विराम के मद्देनजर यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत या पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की घोषणा नहीं की थी। भविष्य में इसका क्या मतलब है इसका पूरी तरह से विश्लेषण करने में समय लगेगा। इस बीच, व्हाट्सएप समूहों पर भेजी जा रही कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए- एक ने कहा कि 'पूर्ण युद्ध' केवल तभी संभव है जब भाजपा 400 सीटें जीते। आतंकी हमले और युद्ध ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन पर किसी को वोट और संसद में सीट मांगनी चाहिए। यह खतरनाक और अपमानजनक है- यह प्रतिक्रिया अति उत्साही, सहानुभूति रखने वालों और पार्टी के समर्थकों से आती है।

ये लोग उस पार्टी को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं जिसका वे समर्थन करना चाहते हैं।

ध्यान दें कि ट्रम्प ने संघर्ष विराम पर बोलते समय भारत और पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा दिया। ट्रम्प ने एक ही समय अस्तित्व में आए दो देशों के संबंध में स्वीकृत डी-हाइफनेशन को मिटा दिया।

नेपाल में न्यायाधीशों को भी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य होगा, संसद में विधेयक लाने की तैयारी

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल सरकार संसद में एक नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालत तक के सभी न्यायाधीशों को अपना संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। अब तक अदालत के न्यायाधीशों को संपत्ति का खुलासा करने का नियम तो था, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था। अब नेपाल के कानून मंत्रालय ने संसद सचिवालय में एक विधेयक को टेबल करने के लिए प्रस्तावित किया है, जिसमें सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों, उच्च अदालत तथा जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों को संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने को अनिवार्य बनाया गया है। कानून मंत्री अजय चौरसिया ने कहा कि जिस तरह से नेपाल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्री एवं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण को सार्वजनिक करना अनिवार्य है, उसी तरह से अब न्यायाधीशों को भी इस दायरे में लाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय भी न्यायाधीशों का संपत्ति विवरण न्याय परिषद में देना अनिवार्य है, पर उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसलिए सरकार के इस नए विधेयक से इसे सार्वजनिक करना अनिवार्य हो जाएगा। नए विधेयक में न्यायाधीशों को अपनी नियुक्ति और स्थानांतरण के 30 दिनों के भीतर ही संपत्ति विवरण को संबंधित अदालत के वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य बनाया जा रहा है।

अमेरिकी सीनेट में विदेशी सहायता और सार्वजनिक प्रसारण में कटौती संबंधी विधेयक पारित

वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के उच्च सदन सीनेट ने सुबह व्हाइट हाउस के विदेशी सहायता और सार्वजनिक प्रसारण पर खर्च पर कटौती के विधेयक को मामूली अंतर से पारित कर दिया। सीनेट के इस कदम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 9.4 बिलियन डॉलर की कटौती करने का रास्ता साफ हो गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार रिपब्लिकन ने कांग्रेस की खर्च करने की शक्ति के सामने समर्पण करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। 51-48 के मतों से यह प्रस्ताव दो रिपब्लिकन की आपत्तियों के बावजूद पारित हुआ। दोनों ने तर्क दिया कि उनकी पार्टी संघीय वित्त पोषण पर कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार का हनन कर रही है। इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों में रिपब्लिकन मेन की सीनेटर सुजैन कोलिन्स और अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की शामिल हैं। उम्मीद है कि सदन इस सप्ताह के अंत में इसे अंतिम मंजूरी देते हुए ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजेगा। इस विधेयक पर बहस ने कांग्रेस की धन-संपत्ति पर चल रही खींचतान को उजागर कर दिया। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से व्हाइट हाउस ने संघीय खर्च पर कटौती के लिए कठोर कदम उठाए हैं। बजट कार्यालय निदेशक रसेल टी. वॉट के नेतृत्व में व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारियों ने संघीय सरकार के आकार पर लगाम लगाने की कोशिश की है। यह राष्ट्रपति के संघीय खर्च पर दूरगामी अधिकार हासिल करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है।

चीन में फंसे 1200 नेपाली नागरिकों की वापसी के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज

काठमांडू। नेपाल और चीन की सीमा पर 8 जुलाई को आई बाढ़ से पुल बह जाने के बाद चीन की तरफ फंसे करीब 1200 नेपाली नागरिकों की वापसी के लिए गुरुवार को कूटनीतिक प्रयास तेज किये गए हैं। बाढ़ से प्रभावित रसुवा सीमा नाका पर बने नेपाल-चीन मैत्री पुल के बह जाने से केरुंग में असहाय हुए नेपाली नागरिकों को जल्द वापस लाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने चीनी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है।रसुवा जिले के प्रमुख जिला अधिकारी अर्जुन पौडेल के अनुसार विदेश मंत्रालय ने चीनी सरकार से फंसे हुए 1,200 लोगों की वापसी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। चीनी पक्ष ने केरुंग में असहाय नेपालियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की है। फंसे हुए लोगों में 91 वाहन चालक और सहायक शामिल हैं। पौडेल ने बताया कि बुधवार को उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्रालय को कूटनीतिक पहल शुरू करने का अनुरोध करते हुए पत्र भेजा था।

इराक में आग लगने से 61 लोगों की मौत, तीन दिन के शोक की घोषणा

बगदाद। इराक के पूर्वी हिस्से में स्थित वासित प्रांत के कुट शहर की एक मार्केट में आग लगने से कम से कम 61 लोगों की मौत हो गई। अनेक लोग लापता बताए गए हैं। नागरिक सुरक्षा टीमों ने कम से कम 45 लोगों को बचा लिया है। वासित प्रांत में तीन दिन के शोक की घोषणा की गई है। अल जजीरा न्यूज चैनल की खबर के अनुसार इराक के गृह मंत्रालय ने कहा कि यह आग कुट शहर के एक हाइपरमार्केट में लगी। 14 जले हुए शव मिले हैं। नागरिक सुरक्षा टीमों ने इमारत के अंदर से 45 लोगों को बचाया है, जबकि 59 मृतकों की पहचान हो गई है। यह हाइपर मार्केट एक पांच मंजिला इमारत में आबाद थी। यहां रात भर आग की लपटें उठती रहीं। इस इमारत में कुछ दिन पहले एक रेस्टोरेंट भी खुला था। प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने कहा कि उन्होंने गृहमंत्री को मौके पर भेजा है। वासित प्रांत के गवर्नर मोहम्मद अल-मायाही ने बताया कि आग हाइपर मार्केट और रेस्टोरेंट में लगी। दमकलकर्मियों ने कई लोगों को बचाया और आग बुझाई।

'मैं नहीं बनाता महिलाओं की फोटो,' ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दी धमकी

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' पर एक कथित अभद्र पत्र के बारे में प्रकाशित खबर को लेकर मुकदमा करने की धमकी दी है। दावा किया जा रहा है कि यह पत्र ट्रंप ने 2003 में जेफरी एपस्टीन को 50वें जन्मदिन पर लिखा था, जिसमें एक महिला का आपत्तिजनक फोटो था। 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' का कहना है कि उसने पत्र की समीक्षा की है, लेकिन कोई फोटो नहीं छापा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की सफाई को लेकर सवाल उठाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मेरे नाम से एपस्टीन को लिखा गया एक फेक लेटर छापा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, न ही मैं ऐसे बोलता हूं, और मैं तस्वीरें भी नहीं बनाता। मैंने रूपर्ट मर्डोक को बताया था कि ये झूठी कहानी है,

फिर भी उन्होंने इसे छाप दिया। अब मैं उनके और उनके अखबार पर केस करूंगा।' ट्रंप और एपस्टीन को लेकर यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब एपस्टीन के यौन शोषण मामले को लेकर प्रशासन के रवैये पर पहले से ही राजनीतिक तनाव चरम पर है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक बयान जारी किया।

उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को निर्देश दिया कि वे इस मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक ग्रैंड जूरी की गवाही को, अदालत की मंजूरी के अधीन, सार्वजनिक करें। ट्रंप ने इस मामले को 'डेमोक्रेट्स द्वारा चलाया गया एक स्कैम' करार दिया और इसे तत्काल समाप्त करने की मांग की। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, जेफरी एपस्टीन को लेकर हो रहे हंगामे को देखते हुए मैंने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी से कहा है कि वे अदालत की मंजूरी के अधीन, ग्रैंड जूरी की सभी जरूरी गवाही पेश करें। डेमोक्रेट्स द्वारा चलाया जा रहा यह स्कैम अभी बंद होना चाहिए।

स्लोवेनिया ने इजराइल के दो मंत्रियों को 'अवांछित' घोषित किया, ईयू में पहली कार्रवाई

एजेंसी

साराजेवो। स्लोवेनिया ने इजराइल के दो कट्टरपंथी मंत्रियों राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच को पर्सोना नॉन ग्राटा (अवांछित व्यक्ति) घोषित किया है। ऐसा करने वाला स्लोवेनिया पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है। यह निर्णय इजराइल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा और उकसावे के आरोपों के चलते लिया गया है।स्लोवेनिया की विदेश मंत्री तान्या फायोन ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ÷आज हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमने दो इजराइली मंत्रियों को स्लोवेनिया में अवांछित घोषित किया है। यह यूरोपीय संघ में अपनी तरह की पहली कार्रवाई है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों मंत्री वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियों के विस्तार, फिलिस्तीनियों की जबरन बेदखली और नागरिक फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ हिंसा के समर्थन में सार्वजनिक बयान देते रहे हैं। फायोन ने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ब्रसेल्स में हुई ईयू विदेश मंत्रियों की बैठक में इजराइल के खिलाफ कोई साझा कार्रवाई तय नहीं हो सकी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य संभावित उपायों पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल विस्तार से कुछ नहीं बताया। इजराइली सरकार की ओर से इस फैसले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि इजराइल पहले भी गाजा में नरसंहार के आरोपों को सिरे से खारिज करता आया है। उसका कहना है कि उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा में है, खासकर 07 अक्टूबर 2023 को हुए हमास हमले के बाद, जिसमें 1,200 लोगों की मौत हुई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था।

अमेरिका की दिग्गज पॉप गायिका और अभिनेत्री कॉनी फ्रांसिस का 87 वर्ष की आयु में निधन

एजेंसी

न्यूयॉर्क। अमेरिका की मशहूर दिग्गज पॉप गायिका और अभिनेत्री कॉनी फ्रांसिस का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। न्यू जर्सी के नेवार्क में 12 दिसंबर, 1937 को जन्मी फ्रांसिस ने एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 1960 के दशक में वह युवाओं और किशोरों की चहेती गायिका रहीं। इस दशक में उनके गाने 'लिपस्टिक ऑन योर कॉलर' और 'हूज सॉरी नाउ?' मौजूदा पीढ़ी ने जमकर सुना। सीएनएन न्यूज चैनल की खबर के अनुसार कॉनी फ्रांसिस के निधन की सूचना दुनिया को सबसे पहले उनके प्रचारक और मित्र रॉन रॉबर्ट्स ने दी। रॉबर्ट्स ने फेसबुक पेज पर लिखा, भारी मन और अत्यंत दुख के साथ मैं आपको कल रात अपनी प्रिय मित्र कॉनी फ्रांसिस के निधन की सूचना दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि फ्रांसिस को हाल ही में दर्द की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस महीने की शुरुआत में उन्हें कुछ कार्यक्रम रद्द भी करने पड़े थे। हाल

में उनके गाने प्रिटी लिटिल बेबी ने टिकटॉक ट्रेंड की बदौलत युवा पीढ़ी का ध्यान आकर्षित किया था। युवावस्था में फ्रांसिस ने आर्थर गॉडफ्रे के लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक स्टारटाइम टैलेंट स्काउट्स में प्रथम पुरस्कार जीता। एमजीएम कंपनी ने सबसे पहले फ्रांसिस का एकल गीत फ्रेंडी रिलीज किया था। फ्रांसिस को बड़े पर्दे पर भी सफलता मिली। उन्होंने 1963 में व्हेयर द बॉयज आर, फॉलो द बॉयज, 1964 में लुकिंग फॉर लव और 1965 में व्हेन द बॉयज मीट द गर्ल्स जैसी फिल्मों में काम किया। व्हेन द बॉयज मीट द गर्ल्स उनकी आखिरी फिल्म थी। फ्रांसिस को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। 1974 में न्यूयॉर्क के वेस्टबरी संगीत मेले में प्रस्तुति के बाद होटल में हुए हादसे को वह कभी नहीं भूल पाईं। होटल में उनके साथ बलात्कार और उन्हें लूटने की कोशिश की गई। उन्होंने इसके बाद होटल पर मुकदमा दायर किया। वह मुकदमा जीत भी गईं, लेकिन इस हमले ने उन्हें गहरे अवसाद में धकेल दिया। तीन साल बाद उनके नाक की सर्जरी की गई। इस कारण फ्रांसिस की आवाज की मिठास चली गई। इससे उबरने में उन्हें लंबा समय लगा। उनके भाई जॉर्ज ए. फ्रैंकोनेरो की 1981 में 40 वर्ष की आयु में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो वकील थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नसों की बीमारी, पैरों में आने लगी सूजन

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप को उम्रजनित शारीरिक दिक्कतें शुरू हो गई हैं। 79 वर्षीय ट्रंप को नसों की बीमारी हो गई है। इससे उनके पैरों में सूजन आने लगी है। व्हाइट हाउस ने जारी बयान में कहा कि ट्रंप के पैरों के निचले हिस्से में सूजन और दाहिने हाथ में चोट के निशान हैं। द वाशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार, व्हाइट हाउस ने आधिकारिक विज्ञप्ति में चिकित्सक के हवाले से कहा कि ट्रंप के शरीर में क्रोनिक शिरापरक की अपर्याप्तता है। यह ऐसी स्थिति होती है जिससे जिसमें पैरों को हृदय तक रक्त पहुंचाने में परेशानी होती है। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा विज्ञान में साफ किया गया है कि क्रोनिक शिरापरक अपर्याप्तता पीड़ित व्यक्ति के पैरों की नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस वजह से रक्त को हृदय तक वापस ले जाने में मुश्किल होती है। इससे पैरों में रक्त जमा हो जाता है। पैरों में रक्त जमा हो जाने से सूजन, दर्द, और त्वचा में परिवर्तन आ जाता है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट संवाददाता

सम्मेलन में कहा कि यह बीमारी आमतौर पर 70 वर्ष से अधिक उम्र के बाद होती है। उन्होंने कहा कि इस इस हफ्ते ऑनलाइन कुछ तस्वीरें वायरल हुईं। इनमें ट्रंप के पैर सूजे हुए और एक हाथ की त्वजा में पारदर्शी आवरण दिखाई दिए। इन तस्वीरों के बाद इंटरनेट पर कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि प्रशासन राष्ट्रपति के बारे में कुछ छुपा रहा है। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति के हाथ में कई लोगों से हाथ मिलाने की वजह से चोट आ गई है। उनके पैर में सूजन एक सामान्य नसों की बीमारी के कारण है। लेविट ने कहा कि इससे राष्ट्रपति को कोई परेशानी नहीं हो रही। लेविट के संवाददाता सम्मेलन के बाद व्हाइट हाउस ने अमेरिकी नौसेना के एक अधिकारी और ट्रंप के चिकित्सक शॉन बारबेला का पत्र जारी किया। इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने इन समस्याओं के संबंध में कई परीक्षण करवाए हैं। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के पैरों के अल्ट्रासाउंड से क्रोनिक वेनस इनसफीशिएंसी का पता चला है, जो आम बीमारी है, खासकर 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है। अन्य जांच में हृदय गति रुकने, गुर्दे खराब होने या किसी अन्य उम्रजनित बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले।

गाजा के कैथोलिक चर्च पर हमले में 3 की मौत, इजरायल ने जताया खेद; पोप और संयुक्त राष्ट्र ने भी की निंदा

एजेंसी

यरुशलम। इजरायल ने गाजा के एकमात्र कैथोलिक चर्च पर हुए घातक हमले पर दुख जताया है। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 10 लोग घायल हुए। हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा के एकमात्र कैथोलिक चर्च पर हुए हमले को लेकर इजरायल गहरा खेद प्रकट करता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि यह हमला टारगेट भटकने के कारण हुआ, जिससे गोला-बारूद होली फैमिली चर्च पर गिरा। उन्होंने कहा, हर एक मासूम जान का जाना एक त्रासदी है। हम पीड़ित परिवारों और विश्वासियों के दुख में सहभागी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) इस घटना की जांच कर रहा है, जिसकी परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं।

मंत्रालय ने आगे कहा कि जांच के परिणाम पारदर्शी रूप से प्रकाशित किए जाएंगे। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की एक प्रवक्ता ने बताया, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी गाजा में होली फैमिली चर्च पर हुए हमले की निंदा की, जोकि आम नागरिकों के लिए एक शरणस्थली था। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख की सहयोगी प्रवक्ता स्टेफनी ट्रेंबले ने कहा, धार्मिक स्थलों पर हमले अस्वीकार्य हैं। शरण चाहने वाले लोगों का सम्मान और सुरक्षा होनी चाहिए, न कि उन पर हमले होने चाहिए। उन्होंने कहा, पहले ही बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। महासचिव सभी पक्षों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि नागरिकों का हर समय सम्मान और सुरक्षा हो और गाजा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता पहुंच सके। स्टेफनी ट्रेंबले ने यह भी कहा कि तत्काल युद्धविराम और सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की सख्त जरूरत है। चर्च पर हमले के बाद पोप लियो 14 ने गाजा में युद्धविराम का अपना आह्वान दोहराया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, गाजा में होली फैमिली कैथोलिक चर्च पर हुए सैन्य हमले में हुई जान-माल की हानि और घायलों के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं पैरिश समुदाय को अपनी आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन देता हूं।

अमेरिकी सोलर कंपनियों ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से होने वाले आयात पर टैरिफ की मांग की

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिका की सौर पैनल निर्माता कंपनियों के एक समूह ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से हो रहे सौर पैनलों के आयात पर टैरिफ (शुल्क) लगाने की मांग की है। इन देशों पर सस्ते दामों पर उत्पादों की बिक्री (डंपिंग) कर अमेरिकी बाजार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका अमेरिकी वाणिज्य विभाग के समक्ष दायर की गई। इस मांग का नेतृत्व 'अलायंस फॉर अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड' नामक समूह कर रहा है, जिसमें फर्स्ट सोलर, दक्षिण कोरियाई कंपनी क्यू-सेल, और निजी कंपनियां टैलोन पीवी और मिशन सोलर शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन देशों की कंपनियों को उनकी सरकारों से अनुचित सब्सिडी मिल रही है और वे अमेरिका में लागत से कम कीमत पर उत्पाद बेच रही हैं, जिससे अमेरिकी निर्माण क्षेत्र को गहरा नुकसान हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि चीनी कंपनियों ने पहले जिन दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया) में उत्पादन किया था, उन पर पहले ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। अब वे कंपनियां अपना उत्पादन इंडोनेशिया और लाओस में स्थानांतरित कर रही हैं। साथ ही भारत की कुछ कंपनियां भी अमेरिकी बाजार में कम कीमत पर पैनल बेच रही हैं। याचिका के मुताबिक, भारत, इंडोनेशिया और लाओस से अमेरिका में सोलर पैनल का आयात वर्ष 2022 में 289 मिलियन डॉलर था।

बांग्लादेश के गोपालगंज में हिंसा में मारे गए लोगों का बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार!

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और गोपालगंज में हुई हिंसा में मारे गए लोगों का बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरकार ने दावा किया है कि लोग अस्पताल से चारों लोगों के शव जबरदस्ती ले गए। ढाका ट्रिब्यून की खबर में परिजनों के हवाले से कहा गया है कि हिंसा के शिकार उनके सदस्यों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। खबर में कहा गया है कि इन लोगों की मौत पर गुरुवार रात तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इस हिंसा की वजह अवामी लीग और उसके प्रतिबंधित छात्र लीग के नेताओं और समर्थकों की नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) की रैली पर हुए कथित हमले को ठहराने की

कोशिश की गई है। ढाका ट्रिब्यून ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा कि हमलावरों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। इसमें कथित तौर पर चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान रमजान काजी, सोहेल राणा, दीप्तो साहा और इमोन तालुकदार के रूप में हुई। पीड़ित परिवारों ने दावा किया कि पुलिस ने उन सभी की गोली मारकर हत्या कर दी। चारों पीड़ितों में से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं किया। इमोन को गुरुवार सुबह लगभग सात बजे गेंतपारा स्थित नगरपालिका कब्रिस्तान में दफनाया गया। सोहेल को भी लगभग उसी समय तुंगीपारा स्थित उनके पारिवारिक कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। रमजान काजी को बुधवार रात नमाज के बाद गेंतपारा में दफना दिया गया। दीप्तो का अंतिम संस्कार रात को नगर निगम के श्मशान घाट पर किया गया। इस बारे में गोपालगंज सामान्य अस्पताल के अधीक्षक डॉ. जिबितेश बिस्वास का कहना है कि चारों के शव अस्पताल लाए गए थे, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि अस्पताल ने कोई मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया। ढाका रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक रेजाउल करीम मलिक ने स्वीकार किया कि शव परीक्षण नहीं किया गया है।

यूक्रेन संकट के बीच जेलेंस्की ने यूलिया स्विरीडेन्को को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, डेनिस शमिहाल होंगे नए रक्षा मंत्री

एजेंसी

कीव। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच थके हुए राष्ट्र को नई ऊर्जा देने के प्रयास में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूलिया स्विरीडेन्को को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री रहीं स्विरीडेन्को, रूस के 2022 के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद नियुक्त होने वाली पहली प्रधानमंत्री हैं। 39 वर्षीय स्विरीडेन्को अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ कूटनीति में अनुभवी हैं। उन्होंने हाल ही में अमेरिका के साथ यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों के विकास संबंधी समझौते में प्रमुख वार्ताकार की भूमिका निभाई थी। साथ ही, उन्होंने युद्धकाल में रूस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की वार्ता में भी अहम भूमिका निभाई थी। स्विरीडेन्को ने संसद से विश्वास मत मिलने के बाद एक्स पर लिखा, युद्ध किसी देरी की अनुमति नहीं देता। हमें तेज और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। सेना के लिए भरोसेमंद आपूर्ति, हथियार निर्माण में आत्मनिर्भरता और रक्षा बलों की तकनीकी क्षमता बढ़ाना हमारी छह माह की प्राथमिकताएं हैं।

इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल, जो मार्च 2020 से पद पर थे, अब नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन घरेलू हथियार उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है और अमेरिका के साथ मिलकर आधुनिक रक्षा प्रणाली विकसित करने पर काम कर रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव को पद से हटाया गया है। यद्यपि उन्होंने मंत्रालय में सुधारों की कोशिश की, लेकिन कई आलोचकों ने उनके कार्यकाल को कुप्रबंधन से प्रभावित बताया। जेलेंस्की ने अमेरिका में यूक्रेन की अगली राजदूत के रूप में ओल्गा स्टेफनिशीना को नामित किया है। वर्तमान में उन्हें अमेरिका के साथ सहयोग विकास की विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। स्टेफनिशीना यूरोपीय एकीकरण मामलों की पूर्व मंत्री रही हैं और वे जेलेंस्की की टीम में एक विश्वसनीय और अनुभवी चेहरा मानी जाती हैं। यूक्रेनी संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा, हम सब जल्द शांति चाहते हैं। लेकिन हमें यह भी दिख रहा है कि वैश्विक समर्थन को बनाए रखना कितना कठिन होता जा रहा है। कई अन्य युद्ध और संकट दुनिया भर में उभर रहे हैं।

सीरियाई राष्ट्रपति ने ड्रूज समुदाय की सुरक्षा को बताया सर्वोपरि

एजेंसी

दमिश्क। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शराआ ने देश के दक्षिणी हिस्से में हिंसा से प्रभावित ड्रूज बहुल शहर सुवैदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय धार्मिक नेताओं और गुटों को सौंपने की घोषणा की है। उन्होंने यह कदम सांप्रदायिक संघर्ष को समाप्त करने और दमिश्क पर इजराइली हवाई हमलों के बाद उत्पन्न हालात के मद्देनजर उठाया है। उन्होंने कहा कि ड्रूज लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। टेलीविजन पर प्रसारित एक संबोधन में राष्ट्रपति अल-शराआ ने कहा कि जो लोग हमारे ड्रूज भाइयों के खिलाफ ज़्यादती और हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा दी जाएगी। वे हमारी जिम्मेदारी में हैं और इस राष्ट्र की सामाजिक संरचना का अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे समाज में विभाजन फैलाने की किसी भी विदेशी या आंतरिक कोशिश को पनपने नहीं दिया जाएगा। शांति बहाली की दिशा में सुरक्षा की जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय हितों के तहत स्थानीय समुदायों को सौंपी जाएगी। उल्लेखनीय है कि सुवैदा और आसपास के क्षेत्रों में बीते कुछ दिनों में ड्रूज सशस्त्र समूहों, बेदुइन जनजातियों और सरकारी बलों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई हैं। इन हिंसा की घटनाओं में दक्षिणी सीरिया में अब तक 169 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने मृतकों की संख्या 360 से अधिक बताई है।

जापान के 'डिफेंस वाइट पेपर' पर भड़का उत्तर कोरिया, 'युद्ध की तैयारी' का लगाया आरोप

सोल। उत्तर कोरिया ने जापान के 'डिफेंस वाइट पेपर' पर सख्त ऐतराज जताया है। दरअसल, इस रक्षा रिपोर्ट में उत्तर कोरिया को 'खतरा' बताया गया है। बिफरे विदेश मंत्रालय ने इसे 'युद्ध की तैयारी'और आक्रामक इरादों वाला कदम करार दिया है। उत्तर कोरिया ने जापान पर आरोप लगाया कि वह खुद को एक सैन्य ताकत बनाने की कोशिश को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है।

नॉर्थ कोरियाई विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले द इंस्टीट्यूट फॉर जापान स्टडीज ने कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के जरिए बयान जारी कर जापान के रक्षा श्वेत पत्र (डिफेंस वाइट पेपर) की निंदा की। ये श्वेत पत्र तीन दिन पहले जापान ने जारी किया था। इस पत्र में उत्तर कोरिया, रूस और चीन को जापान के लिए 'गंभीर खतरा' बताया गया। साथ ही उत्तर कोरिया को रूस से सैन्य सहयोग के बदले परमाणु और मिसाइल तकनीक मिलने की संभावना पर 'गहरी चिंता' जताई गई। उत्तर कोरिया ने अपने बयान में जापान पर फिर से आक्रमण की महत्वाकांक्षा रखने और पूर्वव्यापी स्ट्राइक क्षमता हासिल करने का आरोप लगाया, जिसमें हाल के वर्षों में स्वदेशी लंबी दूरी की मिसाइलों

का विकास और विदेश से ऐसी मिसाइलों की खरीद का हवाला दिया गया। योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बयान में जापान के रक्षा श्वेत पत्र को 'पुनः आक्रमण की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए युद्ध का माहौल पैदा करने' की सोच करार दिया और चेतावनी दी गई कि जापान का सैन्य महाशक्ति बनने का प्रयास क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालता है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान में कहा गया, 'यह जापान की धमकी भरी सत्ता को छिपाने और क्षेत्रीय स्थिति को धीरे-धीरे बढ़ाने वाली उसकी लापरवाह हरकतों को उचित ठहराने का बेशर्मी भरा तर्क है, ताकि पूरे द्वीपसमूह को अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए सैन्य चौकी और लॉजिस्टिक आधार बनाया जा सके। बयान में दावा किया गया कि जापान अब लंबी दूरी के हमले और ट्रांस-डोमेन ऑपरेशन की क्षमता सहित आक्रामक युद्ध की क्षमता विकसित करने में जुटा है और यह मात्र अस्थायी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि 'शांति राज्य' की पहले की नीति से हटकर सैन्य नीति का पुनः अभिविन्यास है। बयान में यह भी कहा गया, 'वर्तमान घटनाक्रम एक बार फिर साबित करता है कि (उत्तर कोरिया) द्वारा अपनी परमाणु युद्ध निरोधक क्षमता को मजबूत करने के प्रयास अमेरिका और उसके सहयोगियों के उकसावे को सख्ती से दबाने में एक अनिवार्य योगदान के रूप में काम करते हैं।' केसीएनए ने एक अलग टिप्पणी में जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली के संयुक्त अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने के प्रोजेक्ट की आलोचना की और इसे जापान के 'युद्ध गठबंधन' को बहाल करने का प्रयास बताया। केसीएनए ने कहा, 'जापान का सैन्य आधुनिकीकरण का षड्यंत्र अपने युद्ध गठबंधन को बहाल करके पिछले साम्राज्यवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश में निहित है। उन्होंने दावा किया कि यह संयुक्त लड़ाकू जेट प्रोजेक्ट आक्रामक युद्ध शुरू करने का रास्ता तैयार करता है।

सुखु सरकार को घेरा हिमाचल परिवहन निगम कर्मचारियों; किया मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से सरकारी कर्मचारी लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करते नजर आ रहे हैं, जिसका कारण कर्मचारियों की मांगों को न माना जाना और उन्हें समय पर कर्मचारियों का हक न मिलना है। इसी के चलते आज हिमाचल परिवहन निगम के कर्मचारियों ने पठानकोट में गेट रैली निकालकर हिमाचल की सुखु सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिमाचल परिवहन निगम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मान सिंह ने बताया कि हिमाचल सरकार कर्मचारियों के साथ धक्का कर रही है। कर्मचारियों को उनका ओवरटाइम नहीं दिया जा रहा है। मेडिकल की अभी तक किश्तें लंबित हैं और सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस समय हिमाचल परिवार निगम की हालत ऐसी है कि वर्कशॉप में बस की मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट तक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पठानकोट में कोई बस खराब हो जाती है, तो विभागीय अधिकारी सबसे पहले यह जाँच करेंगे कि हिमाचल की किस वर्कशॉप में बदलने लायक स्पेयर पार्ट है। फिर वहाँ से स्पेयर पार्ट पठानकोट पहुँचाया जाएगा और फिर बस की मरम्मत करके उसे सड़क पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जल्द ही बकाया किश्तें नहीं मिलीं, तो 1 अगस्त से वह ओवरटाइम नहीं करेंगे और अपनी निर्धारित 8 घंटे की ड्यूटी ही करेंगे।

न्यूज फ्लैश

किसी और के मकान पर कब्जा करने पर पुलिस की करवाई

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

पुलिस ने आज एक बड़ी करवाई को अमल में लाते हुए एक व्यक्ति द्वारा किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसके ऊपर एक और मंजिल का निर्माण कराकर खुद मि मलिकी साबित करने वाले कि इमारत को ही फ्रिज कर दिया गया। इस सम्बंधित जानकारी देते हुए एसपी अशोक रतन ने बताया कि पंजाब - हिमाचल प्रदेश सीमा से सटे चक्की नदी किनारे के गांव छन्नी स्थित एक व्यक्ति शमशेर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह वासी वार्ड 9 डमटाल द्वारा एक मकान पर कब्जा कर रखा था और उस मकान के ऊपर एक और मंजिल का निर्माण कर लिया था जबकि उक्त जायदाद का असल मालिक तिलक राज पुत्र राम प्रकाश निवासी गांव छन्नी पुलिस थाना डमटाल तहसील इंदौरा है जिसके नाम पर उक्त मकान की रजिस्ट्री है मगर इसके बावजूद शमशेर सिंह द्वारा जबरन अपना कब्जा कर लिया गया था। जिस पर सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली के मुताबिक आदेश सी ए/डी एल/एच पी/ एन डी एंड पी एस/ पी ओ एल के द्वारा धारा 68 एफ (2) एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत खाता नं० 28 खतौनी नं० 94 खसरा नं० 176 कुल भूमि माप 0-20-21 एचएम आवासीय मकान शमशेर सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह गांव वार्ड नं० 9 डमटाल त० इन्दौरा जिला कांगडा नें अवैध तौर पर गांव छन्नी में दो मंजिल मकान निर्मित किया है। जो उक्त जमीन का असल मालिक तिलक राज पुत्र श्री राम प्रकाश निवासी गांव व डा० छन्नी त० इन्दौरां जिला कांगडा के नाम पर पंजीकृत है। जिस पर शमशेर उपारोक्त ने अवैध कब्जा कर दो मंजिल मकान निर्माण किया है को आज पुलिस थाना डमटाल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया और मकान के बाहर इस सम्बंधित सूचना बोर्ड लगा दिया गया है।

कृषि विज्ञान केंद्र घोह में डेयरी फार्मिंग का दिस दिवस का प्रशिक्षण 21 जुलाई से शुरू होगा

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

बेरोजगार युवाओं, महिलाओं व किसानों को स्व रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र घोह में दस दिवस का डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण 21 जुलाई से शुरू होगा, जिसके लिए इच्छुक बेरोजगार युवा, महिलाएं, किसान व अन्य लोग आवेदन कर सकते है। यह जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र घोह के एसोसिएट डायरेक्टर डा. बिक्रमजीत सिंह ने देते हुए बताया कि कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की ओर से संचालित कृषि विज्ञान केंद्र घोह में डेयरी फार्मिंग के लिए दस दिवस का प्रशिक्षण 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें युवाओं, महिलाओं , किसानों व अन्य को डेयरी फार्मिंग की बारिकियों के प्रति प्रशिक्षण दे कर उनको अपना रोजगार स्थापित करने में सहयोग दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए आवदेक को 21 जुलाई को सुबह दस बजे अपने पासपोर्ट साइज की फोटो व आधार कार्ड की फोटो कापी जरूर लानी होगी। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण लेने वाले केंडीडेटो को प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएगें।

निर्धन छात्रों की सहायता के लिए पुस्तकालय में बुक बैंक की स्थापना की गई

दिव्य दिल्ली : प्रेम स्वरूप शर्मा (नगरोटा सूरियां)

राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरियां में निर्धन छात्रों की सहायता के लिए पुस्तकालय में ह्यबुक बैंकह्न की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश की जानी मानी शिक्षाविद् एवं साहित्यकार स्वर्गीय प्रो. डॉ. सुतिन्दर डोहरू के पुस्तक संकलन में से उनके परिवार के सदस्यों ने बुक बैंक के लिए दो सौ पुस्तकें दान की। उनके पति श्री सर्वजीत डोहरू एवं उनके सुपुत्र श्री सर्वश्रेष्ठ डोहरू जो हिमाचल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं ,दोनों ने निकट भविष्य में भी बच्चों के लिए और पुस्तकें उपलब्ध करवाने की इच्छा जताई। प्राचार्य प्रो. उपेन्द्र शर्मा ने उनके इस सुकृत्य के लिए आभार जताया एवं इसे प्रो. डोहरू के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताई।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शाहपुर कंडी क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत 20 चालान काटे

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

पंजाब सरकार की और से पंजाब के लोगों की सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए तथा तंबाकूयुक्त बस्तुयों से होने वाली हानी से बचाने के लिए विशेष मुहिम जारी की गई है, जिसके तहत आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रणजीत सागर बांध परियोजना के सरकारी अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डाक्टर डीएन चौधरी, प्रयोगशाला अधिकारी दर्शन सिंह काहलों, कस्तूरी लाल , विशन सिंह , सिकुयरटी स्टाफ व उनकी टीम की और से शाहपुर कंडी, के लोकल एरिया व अन्य स्थानों पर दुकानों पर छापेमारी करके, बीस दुकानदारों के तंबाकूयुक्त बस्तुयों को बेचने पर चालान काट कर जुमार्ना किया। हैल्थ विभाग की टीम के वरिष्ठ डाक्टर डीएन चौधरी ने बताया कि सरकार की हिदायत अनुसार तंबाकूयुक्त बस्तुयों को बेचने के लिए सरकार की और से जारी लाईसैंस जरूरी होना चाहिए तथा कोई भी दुकानदार 18 वर्ष की आयु से कम बच्चे को बीडी , सिगरेट, प्रतिबंधित तंबाकूयुक्त वस्तु व अन्य नशीला पदार्थ नहीं बेच सकता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू व उससे बनी हुई बस्तुयों को बेचने से पहले उससे होने वाले नुकसान के वारे जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाने जरूरी है। खुले में सिगरेट व बीडी नहीं बेच सकते है, स्कूल व कालेज के समीप भी कोई दुकानदार अपनी दुकान पर उक्त तंबाकूयुक्त बस्तुयों व प्रतिबंधित सामान को नहीं बेच सकता है। उन्होंने बताया कि आज उनकी टीम ने पूरे क्षेत्र में छापेमारी करके, बीस दुकानदारों के चालान काट कर उनको जुमार्ना किया है तथा चेतावनी बोर्ड लगाने की विशेष हिदायत जारी की है।

नूरपुर के डूंगा बाजार में किसी वाद विबाद को लेकर क्रॉस एफआईआर फिर बीती रात नूरपुर थाने मे दर्ज

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर नगर परिषद के डूंगा बाजार मे बीती रात एक सैलून की दुकान मे किसी वात को लेकर वाद विवाद इतना अधिक वढ गया कि एक पक्ष सैलून वाले ने अपनी सुरक्षा के लिए गुस्से मे आकर उस्तरे से करणवीर सिंह पर काफी वार कर दिए जिसमे करणवीर पुत्र महेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 घायल हो गया' यह जानकारी नूरपुर डीएसपी विशाल वर्मा ने देते हुए बताया कि शिकायत कर्ता करणवीर सिंह की शिकायत पर यह मुकदमा एफ आई आर नंबर149/25 विभिन्न धारा 126(2).109.118(1) व 352 बी एन एस मे आरोपी अनुज पुत्र अनूप निवासी भड़का कोपड़ा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ' डीएसपी वर्मा ने बताया कि इस मामले में नूरपुर थाने में क्रॉस फिर दर्ज की गई है जिसमें घायल शिकायतकर्ता करणवीर सिंह की हालत को देखकर इसे तुरंत नूरपुर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है' अभी शिकायतकर्ता हॉस्पिटल में उपचारधीन है इस वारदात में घायल को काफी छोटे आई हैं जिसमें पीठ और पेट इत्यादि अस्पताल में घायल कर्मवीर को स्टिचिंग भी लगाए गए मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्यवाही की जाएगी' आरोपी अनुज पुत्र अनूप को मोके पर गिरफ्तार कर लिया गया था जिसका दोपहर वाद पुलिस ने मेडिकल करवाया है 'इसी मामले में दूसरी तरफ अनुज पुत्र अनूप निवासी भडका (कोपड़ा)जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की शिकायत पर करणवीर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 के खिलाफ एफ आई आर 148/25 विभिन्न धारा 332 सी 115(2)(3)(5) बी एन एस दिनांक 18 जुलाई 2025 मे मामला दर्ज किया गया है' शिकायतकर्ता का आरोप यह था कि करणवीर सिंह के साथ कार्तिक में अनीश यह दो साथी दुकान पर आकर झगड़ा करने लगे और दुकान का शीशा भी तोड़ दिया और मुझे सड़क पर लें गये यहां इन्होंने मार पिटाई की ' इस मामले में पुलिस टीम थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान की शिरकत में जांच कर रही है ' लड़ाई का कारण वास्तव मे क्या था पुलिस ने दोनों पक्षों के मामले दर्ज करके मामले की छानबीन आरंभ कर दी है ' पुलिस का पहला कर्तव्य घायल को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना था ' डीएसपी वर्मा ने कहा कि इस मामले में फॉरेंसिक टीम की भी मदद दी गई है ' उधर क्षेत्र में लोगों को कहना है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है'

लखनऊ की विवाहित बेटी पठानकोट में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

लखनऊ की विवाहित बेटी पठानकोट में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ससुराल वालों से अलग होकर किराए के मकान में रह रही है। ससुराल वालों पर जहर देने का आरोप लगया था मामला भी दर्ज हुए मगर नहीं हो रही सुनवाई।एक ओर जहाँ आज के दौर में बेटियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, इसलिए इस महंगाई के दौर में वे भी अपने परिवार को सही दिशा में ले जाने में योगदान दे सकती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं के काम को गलत मानते हैं और ऐसा ही कुछ पठानकोट में देखने को मिल रहा है, जहाँ शादी के बाद लखनऊ से पठानकोट आई एक बेटी आज खून के आँसू रोने को मजबूर है। यह बेटी 10 साल पहले शादी के बाद पठानकोट आई थी। ससुराल वाले पहले 2-3 साल तक तो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिससे मजबूर होकर बेटी को घर छोड़कर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी, लेकिन सरकार के जरिए ससुराल वालों से समझौते के अलावा कुछ नहीं हुआ।

लाल चंद ने डेरा बाजीगर बस्ती तारागढ़ में डीप बोर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया

दिव्य दिल्ली करुनीत रंधावा (पठानकोट)

आज कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री लाल चंद कटारूचक ने बाजीगर बस्ती तारागढ़ में डीप बोर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों ने कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री लाल चंद कटारूचक का आभार व्यक्त किया और कहा कि पिछले 40 वर्षों से किसी भी सरकार ने उनकी स्वच्छ पेयजल की मांग पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने डीप बोर का कार्य शुरू करने के लिए कैबिनेट मंत्री पंजाब और आम आदमी पार्टी सरकार का आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा सर्वश्री नरेश कुमार सैनी, जिला अध्यक्ष बी.सी. विंग पठानकोट, पवन कुमार फौजी ब्लॉक अध्यक्ष, संदीप कुमार ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच रोजी सैनी, राजेस कुमार काका, जोगिंदर माजरा, जोगिंदर, रमन भाकरा, सरपंच निसा सैनी बेगोवाल, फौजा राम और अन्य आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए, श्री लाल चंद कटारूचक्क कैबिनेट मंत्री पंजाब ने कहा कि आज वह भोआ विधानसभा क्षेत्र के तारागढ़ गांव के डेरा बाजीगर बस्ती में पहुंचे हैं। यहां लंबे समय से पेयजल संकट था और लोगों को स्वच्छ पेयजल न मिलने के कारण भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, लगभग 2 साल पहले, इस क्षेत्र में एक डीप बोर करवाने के लिए पंचायत को 7 लाख रुपये दिए गए थे और अब एक नई पंचायत बनने के बाद, डीप बोर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

महिला और बच्चों का 30 दिन बीत जाने पर भी नही लगा कोई सुराग

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

पुलिस थाना इंदौरा में गत 23 जून को बलविंदर सिंह पुत्र साधु राम निवासी सनोर ने अपनी पत्नी व दो बच्चों के घर जाने के बाद से संधिग्ध रूप में गुम होने की सूचना दर्ज कराई थी। मगर करीब एक माह के बाद भी उनका कोई सुराग न मिलने पर पति दर दर भटक रहा है। महिला के पति बलविंदर सिंह पुत्र साधु राम निवासी सनोर ने बताया कि उसके 2 लड़के जिसका नाम राघव जोकि 11 वर्ष का है और छोटा आदित्य 7 वर्ष का है। 19 जून को मेरी पत्नी बोली कि उसने अपने चाचा के घर शाहपुरकंडी (पठानकोट) में कुछ दिन रहने के लिए जाना है और रहकर वापस आ जाएगी। वह दोनों लड़कों व पत्नी शुभरानी को सनोर से इंदौरा बस स्टैंड लेकर आया और 11 बजे पठानकोट जाने वाली एचआरटीसी. बस में बैठाकर घर आ गया और फिर उसी दिन समय करीब 1.30 बजे पत्नी का फोन आया और बोली कि वह कुछ ही देर में चाचा के घर में पहुंचने वाली है। उसके बाद मैंने फोन किया तो फोन बंद आता रहा। मैंने तीनों की तमाम रिश्तेदारों के घरों में तलाश की पर उस दिन से कोई भी पता नहीं चला है। उन तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाना इंदौरा में 23 जून को दर्ज करवाई है। उधर इंदौरा पुलिस द्वारा कहा गया कि उक्त के बारे में कोई सूचना हो तो थाना इंदौरा पर सूचित करें।

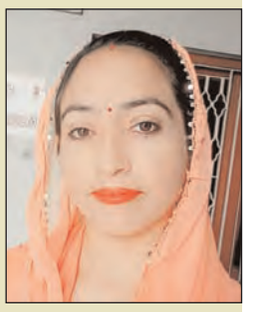

प्रेंजटेशन पब्लिक स्कूल जॅख जुगियाल में बच्चों ने बौद्धिक विकास व तकनीकी ज्ञान के लिए अलग अलग प्रोजेक्टों की प्रदर्शनी लगाई

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

प्रेंजटेशन पब्लिक स्कूल जॅख जुगियाल में स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमति रेणु शर्मा व अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा की देखरेख में स्कूल के स्टुडैंटस के बौद्धिक विकास , तकनीकी ज्ञान की जानकारी, कलाकृतियों को बनाना व अन्य प्रकार के माडलों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में स्टुडैंटस के अभिभावकों ने भी बढ चढ कर भाग लिया। इस प्रदर्शन में स्टुडैंटस ने रचनात्मक कलाकृतियों के साथ, तकनीकी ज्ञान के माडल, प्रोजेक्टस,की प्रदर्शनी लगा कर अन्य स्टुडैंटस को प्रेरित किया। इसके साथ ही स्टुडैंटस ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए कला, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान व अन्य विषयों के ऊपर भी अपना फोकस रखा। प्रदर्शनी में स्टुडैंटस की ओर से बनाई हुई आर्कषक पेंटिंग, माडल व अन्य कलाकृतियों को देख कर बच्चों के अभिभावक व स्टाफ प्रसन्न हुया। इस प्रदर्शनी का मकसद बच्चों में कलात्मक व रचनात्मक गुणोंकी जानकारी प्रदान करना है ताकि बच्चों के बौद्धिक विकास में बढौतरी हो सके। इस अवसर पर स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमति रेणु शर्मा, अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, वाइस चेयरपर्सन निवेदित्ता संधू, प्रिंसीपल रविंद्र कौर, वाइस चेयरपर्सन रेणुका त्रिखा, रजनी वालिया, एकता, परमिंदर ,सोनिया काटल, रश्मी, भावना, कुमार सोनू, परमजीत सिंह, अमित कुमार, सलोनी, टीना, मोहनी, सीनाक्षी, नरेंद्र सिंह, बविता, पूजा व अन्य उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत : प्रो. चन्द्र

दिव्या दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने आज ज्वाली स्थित लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को प्राथमिकता दे रही है।उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने कर्नाटक में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर विस्तार से चर्चा की गई' उन्होंने कहा कि सामाजिक संतुलन और समावेशी नीति निर्माण के लिए वर्तमान जनसंख्या संरचना की सटीक जानकारी आवश्यक है,ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र वर्गों तक सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सुखाश्रय योजना,सुख शिक्षा योजना,यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना,स्वर्ण जयंती आश्रय योजना,अंतजार्तीय विवाह पुरस्कार योजना,कंप्यूटर एप्लिकेशन एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम छात्रवृत्ति योजना,राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना,अनुवर्ती कार्यक्रम, दिव्यांग छात्रवृत्ति, दिव्यांग विवाह अनुदान योजना,शगुन योजना जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।प्रो. चन्द्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है

पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद ने नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान के दौरान भोआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों का दौरा किया

दिव्य दिल्ली : करुनीत रंधावा (पठानकोट)

पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में पंजाब में नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति यात्रा के दूसरे चरण को एक बार फिर लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और लोग सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को पूरा समर्थन दे रहे हैं। यह बात पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने आज नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान के अंतर्गत भोआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में आयोजित नशा उन्मूलन अभियान के दौरान कही। इस अवसर पर सर्वश्री नरेश सैनी, जिला अध्यक्ष बीसी विंग पठानकोट, पवन कुमार फौजी ब्लॉक अध्यक्ष, खुशबीर काटल और आम आदमी पार्टी के अन्य उम्मीदवार भी उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत आज भोआ विधानसभा क्षेत्र के अनूप सेहर, खुशी नगर, झेला आमदा स्कारगढ़, सिहोरा कल्हण और सिहोरा खुर्द गांवों में नशा उन्मूलन अभियान चलाया गया और लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई।इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग अभियान का दूसरा चरण चल रहा है और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम हर दिन विधानसभा क्षेत्र के 5-7 गांवों में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर हमें पंजाब को रंग-बिरंगा पंजाब बनाना है तो नशे को जड़ से खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि जब लोग इस अभियान में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो और भी खुशी होती है।

उन्होंने कहा कि आज विभिन्न गाँवों में पहुँचने पर एक बात सामने आई कि अनूप सेहर गाँव में ग्रामीणों ने यह विश्वास दिलाया है कि गाँव का एक भी युवा नशे का आदी नहीं है।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किया जिला स्तरीय नागनी माता मेले का शुभारंभ

दिव्य दिल्ली : विनय महाजन (नूरपुर)

नूरपुर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आज भव्य शोभायात्रा के साथ जिला स्तरीय नागनी माता मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को मेले की शुभकामनाएं दीं और कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक मेले हमारी लोक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।उन्होंने कहा कि वे गत वर्ष भी इस मेले में सम्मिलित हुए थे और यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मंदिर कमेटी ने इस बार स्वच्छता की दृष्टि से विशेष प्रगति की है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि मेला अवधि तक स्वच्छता की यह व्यवस्था बनी रहे। उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय पंचायत का इस मेले को सफल बनाने में सराहनीय सहयोग है।उपायुक्त ने मंदिर परिसर में किए गए विकास कार्यों की भी सराहना की, जिनमें भंडारा स्थल, भजन-कीर्तन मंच और संपर्क मार्गों का विकास प्रमुख हैं। उन्होंने मंदिर कमेटी से आग्रह किया कि भविष्य में जनकल्याण से जुड़े कार्यों में भी योगदान दें। विशेष रूप से, उन्होंने टीबी रोगियों को पोषण किट प्रदान करने के लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय को सहयोग देने और निक्षय मित्र बनने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता में जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। बारिश के मौसम को देखते हुए उपायुक्त ने मंदिर कमेटी और पंचायत को जल निकासी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि दुकानदारों और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने नागनी पंचायत को सुझाव दिया कि वह 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सैनिटाइजेशन से संबंधित मद में बजट का प्रावधान करे ताकि मंदिर परिसर में सफाई से संबंधित और कार्य किये जा सकें।उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि मेले के दौरान उत्पन्न कूड़े-कचरे का निपटान पद्रैहड़ स्थित कचरा संयंत्र में सुनिश्चित किया जाए।

अनुपमा के ऑन स्क्रीन पति अनुज से इश्क लड़ा चुकी हैं

यामी गौतम

16 साल पहले घर-घर में हुई थी चर्चा

छोटे पर्दे के कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी धाक जमाई है. उन्हें बड़े पर्दे पर भी उतना ही प्यार मिला, जितना की टीवी शो के जरिए मिला था. ऐसी ही एक पॉपुलर एक्ट्रेस यामी गौतम भी हैं. ज्यादा लोगों को शायद पता न हो, लेकिन यामी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी. आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा. साल 2009 में यामी ने 'ये प्यार ना होगा कम' नाम के एक मशहूर शो में काम किया था. वहीं, इस शो में उनके साथ अनुपमा फेम अनुज कपाड़िया यानी गौरव खन्ना लीड रोल में नजर आए थे.'ये प्यार ना होगा कम' 28 दिसंबर 2009 से 2 सितंबर 2010 तक ऑन एयर हुआ था. इसमें यामी गौतम और गौरव खन्ना लीड किरदारों में थे. शो की कहानी दो अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आए दोनों लीड किरदारों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो प्यार में पड़ जाते हैं और साथ रहने के लिए सामाजिक रूढ़ियों से जूझते हैं. गौरव ने अबीर बाजपेयी का किरदार निभाया था, जबकि यामी ने लहर माथुर का किरदार निभाया था.

छोटे पर्दे पर किया गौरव-यामी ने रोमांस

शो की कहानी के मुताबिक, अबीर (गौरव खन्ना) घर का लाड़ला बेटा है, जिसे लाड़-प्यार से पाला गया है और लहर अपने परिवार की एक लाड़ली और स्वतंत्र बेटी है. इस कहानी ने दर्शकों को खूब इंस्पायर्ड किया और यह टेलीविजन पर एक पॉपुलर शो बन गया. यामी के किरदार को घर-घर में पसंद किया गया था.

उनकी खूबसूरती पर फैन्स फिदा हो गए थे. उस दौरान सोशल मीडिया का जमाना तो नहीं था, लेकिन की दिलचस्प कहानी के चलते इसकी चर्चा होती ही रहती थी.

टीवी के इन शो में नजर आ चुकी हैं यामी

गौरव खन्ना और यामी गौतम के बीच की कैमिस्ट्री को दर्शकों खूब पसंद किया था. दोनों को साथ में देखना फैन्स को काफी अच्छा लगता था.

'ये प्यार ना होगा कम' के अलावा, यामी ने 'चांद के पार चलो', 'राजकुमार आर्यन' जैसे कई टीवी शो में भी काम किया है. साल 2012 में यामी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया. उनकी पहली फिल्म आयुष्मान खुराना के साथ 'विकी डोनर' थी. यानी ने आगे चलकर 'उरी' और 'काबिल' जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया.

आंखों की गुस्ताखियां फेल, मालिक की भी ना चली, सुपरमैन की आंधी में बह गया बॉलीवुड-साउथ

बॉक्स ऑफिस के मैदान पर साल 2025 की जंग काफी रोचक नजर आ रही है. इस दौरान कई सारी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया है. मौजूदा समय की बात करें तो बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के कॉम्पिटिशन के बीच हॉलीवुड बाजी मारता नजर आ रहा है. ना तो राजकुमार राव की मालिक में कोई दम नजर आया और ना तो करियर की शुरुआत करने वाली शनाया कपूर की आंखों की गुस्ताखियां ही कुछ कमाल कर सकी. वहीं पिछले 2 हफ्ते के अंदर साउथ में रिलीज हुई कुछ फिल्मों का कलेक्शन भी कोई बड़ा कमाल नही कर सका. ऐसे में फायदा सीधे तौर पर हॉलीवुड फिल्म को मिल रहा है. हालिया रिलीज फिल्म सुपरमैन की कमाई आपको हैरान कर देगी. फिल्म आने वाले वक्त में भी बड़ा तहलका कर सकती है.

बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल कैसा ?

मौजूदा समय में दो बॉलीवुड की फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हैं. जहां एक तरफ सैकनिल्क की रिपोर्ट्स की मानें तो मालिक फिल्म ने 6 दिन में 19.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. जबकी इसका बजट 50 करोड़ रुपए का है. ऐसे में इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती. लेकिन इसकी तुलना में शनाया कपूर की आंखों की गुस्ताखियां फिल्म का हाल तो और भी बुरा है. इस फिल्म का बजट 20 करोड़ के करीब है और सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने 1.68 करोड़ कमाए हैं. मतलब कि ये फिल्म 6 दिन में 2 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर सकी है.

साउथ की फिल्में कैसा परफॉर्म कर रहीं ?

वहीं साउथ की दो नई फिल्में सिनेमाघरों में इस हफ्ते रिलीज हुईं. द 100 और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म ओह बामा अय्यो रामा भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी हैं. वहीं धनुष की कुबेरा और विष्णु मांचू की कन्नप्पा में भी अब कोई दम नहीं रह गया है.

सुपरमैन की आंधी में बह गए सभी

वहीं हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन की बात करें तो इस फिल्म ने मौजूदा समय में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने 6 दिन में ही 30.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. इस कलेक्शन को काफी अच्छा माना जा रहा है. फिल्म का बजट 1886 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है. और ताज्जुब की बात तो ये है कि अपने पहले वीकेंड में भी फिल्म के दुनियाभर का कलेक्शन बजट के करीब पहुंच गया था.

आप शर्त तब रख सकते हैं...दीपिका पादुकोण के 'स्पिरिट' छोड़ने पर राम कपूर का रिएक्शन

900 करोड़ी 'एनिमल' के फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' लगातार चर्चा का हिस्सा बनी हुई है. फिल्म में प्रभास लीड रोल में हैं, वही हीरोइन के लिए दीपिका पादुकोण को फाइनल किया गया था. लेकिन 8 घंटे की मांग पूरी न होने पर दीपिका ने इस फिल्म को छोड़ दिया. दीपिका की डिमांड पर अब बॉलीवुड में एक बहस छिड़ गई है. हर कोई इस पर अपनी राय पेश कर हुआ नजर आ रहा है. कुछ लोग एक्ट्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि प्रोड्यूसर के करोड़ों पैसों का सवाल होता है. इसी बीच अब राम कपूर ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया है.

फर्स्टपोस्ट से बात करते हुए, बड़े अच्छे लगते हैं फेम राम कपूर ने अपने लंबे एक्सपीरियंस और फिल्म इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर बात की. राम ने साफतौर पर कहा, एक बार जब आप शोबिज़ में सक्सेस हासिल कर लेते हैं, चाहे स्टार के रूप में या एक्टर के रूप मेंज्और लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो हां, आप यह चुनने की स्थिति में होते हैं कि आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं.

मैं लकी रहा हूं- राम कपूर

एक्टर ने आगे कहा कि जब मैं टेलीविज़न में काम कर रहा था, तब मैं भी यह तय करता था कि मुझे कितने घंटे काम करना है. इसलिए मैं लकी रहा हूं. कोई भी व्यक्ति जो उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां उसे काम ढूंढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वह चुनाव करने की स्थिति में होता है. इसके अलावा राम ने किसी प्रोजेक्ट को साइन करने के बाद उसकी कमीटमेंट्स पर भी ध्यान देने की बात कही.

राम कपूर बोले, हम में से ज़्यादातर कलाकार, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जानते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्ट पर साइन करते हैं, तो हमें उस प्रोजेक्ट को अपनी पूरी क्षमता से करना होता है. यही तो असल बात है. अपने टीवी के दिनों को याद करते हुए, राम ने बताया कि उन्होंने भी एक बार अपने लिए आठ घंटे की सीमा तय की थी. टीवी लगातार चलता था. कोई सीज़न नहीं था. यह हर दिन, हर महीने, सालों तक चलता था.

फिल्मों और ओटीटी ने बदला वक्त

अपनी बात को पूरा करते हुए राम ने बताया कि मैंने कहा, 'मैं दिन में सिर्फ आठ घंटे काम करूंगा. लेकिन अब फिल्मों और ओटीटी शोज़ के साथ, मिस्त्री की तरह, मैं कभी-कभी दिन में 14 से 16 घंटे काम करता हूं, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के लिए. और मेरे पास शिकायत करने की कोई वजह नहीं है. यह इंडस्ट्री कठिन है, घंटे लंबे हैं, लेकिन मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं वही कर रहा हूं जो मुझे पसंद है.

ये अक्षरा सिंह कौन हैं...भोजपुरी एक्ट्रेस का नाम सुनते ही क्यों भड़क गई थीं

डिंपल सिंह

फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करतीं, लेकिन जब आमने-सामने मिलती हैं तब लगता है कि वो अच्छी दोस्त हैं. इस तरह की चीजें तो हर इंडस्ट्री में है, लेकिन ऐसा भोजपुरी सिनेमा में भी देखने को मिलता है. इस इंडस्ट्री में दो ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो एक-दूसरे को खास पसंद नहीं करती हैं. यहां बात एक्ट्रेस डिंपल सिंह की करने जा रहे हैं, जिनसे जब अक्षरा सिंह का नाम पूछा गया तो उन्होंने अक्षरा को पहचानने से ही इनकार कर दिया था. एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया इसका भी जवाब इंटरव्यू में दिया था.भोजपुरी एक्ट्रेस निधी झा मिश्रा अब यूट्यूब पर अपन शो चलाती हैं जहां सितारे इंटरव्यू देते हैं और कई बड़े खुलासे भी होते हैं. ऐसा ही एक इंटरव्यू निधी ने डिंपल सिंह का भी किया था. इस दौरान उन्होंने खेसारी से लेकर पवन सिंह तक सभी की बातें कीं और जब अक्षरा का नाम आया तो उन्होंने इसपर क्या कहा, आइए जानते हैं.

अक्षरा सिंह को लेकर क्या बोलीं डिंपल सिंह ?

इस इंटरव्यू में निधि मिश्रा ने कई नाम लिए और कहा कि ये सुनकर पहला थॉट आपको क्या आता है. कई नाम लेने के बाद अक्षरा सिंह का नाम भी लिया. इसपर डिंपल सिंह ने कहा, 'कौन?' तो निधी ने फिर से कहा अक्षरा सिंह, तो डिंपल ने थम्सअप करते हुए कहा था, 'बहुत अच्छी हैं.' इसपर निधी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब इस तरह से आप क्यों बोलीं ?

तो डिंपल सिंह ने जवाब दिया था, 'थी कुछ वजह, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उनसे मेरे बारे में पूछा गया तो वो बोलीं डिंपल सिंह कौन है. मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत छोटी है और सभी एक-दूसरे को जानते हैं. मैंने खेसारी जी और पवन जी के साथ काम किया है तो वो जरूर ही मुझे जानती हैं, लेकिन मुझे छोटा दिखाने के लिए कह दिया कि मैं कौन हूं. ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, फिर भी मैं उन्हें यही कहूंगी कि वो अच्छी हैं, बस.'

डिंपल सिंह ने किए हैं कई हिट म्यूजिक एल्बम

एक्ट्रेस डिंपल सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. जिन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, लेकिन डिंपल के चर्चे उनके म्यूजिक एल्बम से ज्यादा होते हैं. डिंपल पवन सिंह की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और उसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पवन सिंह एक कमाल के सिंगर हैं और साथ ही एक अच्छे इंसान भी हैं जो लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटते.

यूपी में 18 की मौत, राजस्थान में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित

उत्तराखंड-हिमाचल और बंगाल व केरल में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली/एजेंसी

देश के कई राज्यों में मानसून ने जबरदस्त कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश से जुड़े हादसों में 18 लोगों की जान चली गई, जबकि राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग (आईएमडी) ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली में क्या है मौसम विभाग का अनुमान?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में गरज के साथ बूंदाबांदी या बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं शनिवार सुबह का न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। जबकि शाम 5.30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 83 प्रतिशत दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शाम 6 बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता "संतोषजनक" श्रेणी में दर्ज की गई, जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 56 था।

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से जानलेवा हादसे

उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण हुई घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें 17 और 18 जुलाई के बीच हुईं हैं। जिसमें से

आठ लोग डूबने से मरे हैं, दो लोगों की मौत सांप के काटने से हुई। वहीं जिलेवार बात करें तो चित्रकूट में दो, मुरादाबाद में तीन, गाजीपुर में एक व्यक्ति की पानी में डूबने के कारण मौत हुई है। जबकि बांदा जिले में तीन, महोबा में दो और ललितपुर में एक व्यक्ति की जान बारिश से जुड़ी घटनाओं में गई।

राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात

राजस्थान के कई जिलों में बीते 24 घंटों में हुई भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बारिश के कारण अजमेर, पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर और पाली जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। टोंक जिले के गोलरा गांव में 17 लोग बानस नदी में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं अजमेर की अना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है, लोग रेत से भरे बोरे रखकर पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बारिश बूंदी जिले के नैनवा में 234 मिमी, नागौर के मेड़ता शहर में 230 मिमी, और अजमेर के मंगल्या वास में 190 मिमी रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार, जोधपुर डिवीजन में आज भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि जयपुर, कोटा और बीकानेर में बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। 27-28 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में फिर से भारी बारिश लौट सकती है।

उत्तराखंड में मौसम का रेड अलर्ट जारी

उत्तराखंड में रविवार को कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून, टिहरी और पौड़ी के साथ-साथ बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं।

हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की यात्रा पर रोक लगाने के आदेश

हिमालय की ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों की यात्रा पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट

वहीं, हिमाचल प्रदेश के नौ जिलों में सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसमें हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, और सिरमौर जिले शामिल हैं। बारिश और लैंडस्लाइड समेत तमाम घटनाओं के कारण राज्य में अब तक 141 सड़कें बंद, 58 जल आपूर्ति योजनाएं और 28 पावर ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। इस कड़ी में मंडी जिले में 94 और कुल्लू में 33 सड़कें बंद हैं।

केरल में उत्तर जिलों में रेड अलर्ट

केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों और जलाशयों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी हो चुकी है। वहीं, कोझिकोड और वायनाड में शुक्रवार रात भारी बारिश हुई, शनिवार सुबह थोड़ी राहत मिली। जबकि अन्य जिले जैसे

एनार्कुलम, इडुक्की, त्रिशूर और पलक्कड़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है।

अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भूस्खलन से जनजीवन बाधित

अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में लगातार बारिश से कई जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया है। जानकारी के मुताबिक, आलो-लिकाबाली सड़क कई स्थानों पर भूस्खलन से बंद हो गई है। एनएचआईडीसीएल (राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचा विकास निगम) को मलबा हटाने में परेशानी हो रही है क्योंकि इलाके में लगातार बारिश हो रही है। उधर, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच नेशनल हाईवे-10 पर भी भूस्खलन और पत्थर गिरने से यातायात रुका हुआ है। कालिम्पोंग जिले के बिरिक दारा में मलबा हटाने का कार्य जारी है, उम्मीद है कि 24 घंटे में रास्ता साफ हो जाएगा।

दरबार साहिब में बम धमाके की धमकी भरी आठवीं मेल आई

चंडीगढ़/एजेंसी

अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ने की धमकी एक बार फिर से मिली है। यह धमकी शनिवार को ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। पिछले 6 दिनों में आठ बार ईमेल के माध्यम से स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। शनिवार को मिली धमकी के बाद पंजाब पुलिस के अलावा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) भी सतर्क हो गई है। अमृतसर सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां कुछ क्षेत्र बीएसएफ के अधीन आता है। अब बीएसएफ ने दरबार साहब परिसर में अपनी गश्त बढ़ा दी है। दरबार साहब में लगातार मिल रही धमकियों के बाद यहां पहुंचे पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता श्वेत मलिक ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के समक्ष उठा दिया है। इस बीच अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने केंद्र व राज्य पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कुलदीप सिंह ने कहा है कि सरकारी जांच एजेंसियां असल आरोपितों तक नहीं पहुंच पाई हैं। यह आश्चर्यजनक बात है। इस मुद्दे पर पहली बार मीडिया के सामने आए जत्थेदार ने कहा है कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए आरोपित से क्या पता चला है ? और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है?, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इन घटनाओं से दरबार साहब की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी आशंकाएं पैदा हो रही हैं।

गरीब रथ एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, बाल-बाल बचे यात्री

अजमेर/एजेंसी

अजमेर-ब्यावर रेल मार्ग पर शनिवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मुंबई से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस (12216) के इंजन में अचानक आग लग गई। यह हादसा अलसुबह सेंदड़ा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। तेज गति से दौड़ती ट्रेन में अचानक धुआं उठता देख लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। जानकारी के अनुसार, जैसे ही सेंदड़ा स्टेशन के पास पहुंची लोको पायलट को इंजन के पिछले हिस्से में धुआं उठता दिखा। उन्होंने तुरंत ट्रेन रोक दी और वायरलेस से कंट्रोल रूम को सूचना दी।

सीएम नीतीश ने पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया

पटना/एजेंसी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने जेपी गंगा पथ पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विकसित किए जा रहे पार्क का भी मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने जायजा लेने के क्रम में पटना सिटी के कंगन घाट से दानापुर के नासरीगंज घाट तक गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ पर एलसीटी घाट से गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेने के बाद एनआईटी घाट पहुंचे जहां उन्होंने गंगा नदी के बढ़े जलस्तर एवं

तटीय इलाकों के वर्तमान स्थिति की पूरी जानकारी अधिकारियों से ली। एनआईटी घाट से जेपी गंगा पथ होते हुए मुख्यमंत्री कंगन घाट के बाद दीघा घाट और दानापुर स्थित नासरीगंज घाट पहुंचकर गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का भी जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट रहें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहें। ताकि लोगों को बाढ़ के पानी से होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी के तटीय इलाकों खासकर निचले क्षेत्रों की स्थिति की लगातार समीक्षा करते रहें और जरूरत पड़ने पर तत्काल रूप से आवश्यक कार्रवाई करें ताकि कोई नुकसान न हो।

नासरीगंज घाट, गांधी घाट सहित कई स्थानों पर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तथा नदी की धारा भी बहुत तेज है।

अदालतें पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाती रही हैं : मुख्य न्यायाधीश गवई

नई दिल्ली/एजेंसी

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सहित देश की तमाम अदालतें हमेशा से पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाती रही हैं। 1996 का टीएन गोडावर्मन केस एक ऐतिहासिक फैसला रहा, जिसमें पहली बार वन की परिभाषा दी गई और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगी। यह बात उन्होंने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के 20 न्यायाधीशों के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए कही। यह आयोजन वन महोत्सव

2025 के तहत दिल्ली सरकार द्वारा पीबीजी ग्राउंड दिल्ली रिज क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर वृक्षारोपण स्थल को न्याय वाटिका नाम दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीश्री नरसिम्हा, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस केवी विश्वनाथन, जस्टिस एसवीएन भाटी, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस पीबी वराले, जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह, जस्टिस मनमोहन, जस्टिस जॉयमाला बागची, जस्टिस एनवी अंजरिया, जस्टिस विजय विश्नोई और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर ने ' एक पेड़ मा के नाम' अभियान में हिस्सा लेकर पौधारोपण किया।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने अपने संबोधन में कहा कि अक्तूबर आते ही दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चिंता की स्थिति बन जाती है। इस दौरान निर्माण कार्य पर रोक लगने से कई बार हजारों मजदूरों की आजीविका पर असर पड़ता है। इसका स्थायी समाधान जरूरी है।

मेरे लिए देश पहले, पार्टी बाद में: शशि थरूर

कोच्चि/एजेंसी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. शशि थरूर ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि उनके लिए 'देश पहले है, पार्टी बाद में।' उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक दल देश को बेहतर बनाने का जरिया होते हैं और सभी पार्टियों को उस मकसद तक पहुंचने के अपने-अपने तरीके अपनाने का हक है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर कोच्चि में शांति, सौहार्द और राष्ट्रीय विकास विषय पर आयोजित एक निजी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

देश पहले, पार्टी बाद में- कांग्रेस सांसद

शशि थरूर ने कहा, 'आपकी पहली निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? मेरे हिसाब से देश के प्रति। राजनीतिक दल देश को बेहतर बनाने का एक माध्यम होते हैं। सभी पार्टियों का एक ही उद्देश्य होता है, देश को आगे ले जाना, भले ही तरीका अलग हो।' उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में सीमा से जुड़े मुद्दों और सशस्त्र बलों के मामलों में सरकार और फौज का समर्थन किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, 'मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये देश के हित में सही है।'

'राष्ट्र हित में सभी दलों को साथ आना चाहिए'

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि लोकतंत्र में राजनीति एक तरह की प्रतियोगिता होती है। 'हम अपने दलों की विचारधाराओं और मूल्यों का सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कभी-कभी अलग-अलग पार्टियों को भी मिलकर काम करना चाहिए। पर कई बार पार्टियां इसे अपने प्रति बेवफाई समझ लेती हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है।' उन्होंने यह भी कहा कि वे राजनीति में देश की सेवा के उद्देश्य से ही लौटे थे और कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति के अंदर और बाहर, दोनों तरीकों से देश के लिए योगदान दे सकें।

'मुझे कांग्रेस हाईकमान से कोई समस्या नहीं'

वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कांग्रेस हाईकमान से कोई दिक्कत है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, 'मैं यहां राजनीति या किसी विवाद पर बात करने नहीं आया हूं।

मैं सिर्फ दो भाषण देने आया हूं,

'प्रोफेसर ही होंगे मेरी मौत के जिम्मेदार...', सुसाइड नोट लिख ज्योति ने की खुदकुशी

नई दिल्ली/एजेंसी

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के छात्रावास में एक छात्रा ने शुक्रवार रात पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका की पहचान लोक विहार, फेज श्री, गुरुग्राम निवासी ज्याति शर्मा के रूप में हुई है। वह बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी।

छात्रा के साथ लगातार हो रहा था अभद्र व्यवहार

पीड़ित परिवार का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के प्रोफेसर द्वारा छात्रा के साथ लगातार अभद्र व्यवहार किया जा रहा था। जिससे तंग आकर छात्रा ने आत्महत्या की है। इसकी जानकारी छात्रा ने कई बार अपने परिवार के लोगों को भी दी थी।

छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले लिखे सुसाइड नोट में भी इसका जिक्र किया है। जिससे गुस्साए पीड़ित स्वजन संग छात्रों ने शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

कुख्यात चंदन हत्या मामले में छह आरोपित गिरफ्तार

पटना/एजेंसी

पटना के बेली रोड पर स्थित पारस एमआरआई अस्पताल में बीते गुरुवार को चंदन मिश्रा हत्या मामले में पटना पुलिस और बंगाल एसटीएफ ने शनिवार को कोलकाता के सैटेलाइट टाउनशिप में एक आवासीय परिसर से छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बंगाल एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक इन आरोपितों को शनिवार तड़के पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की संयुक्त रूप से की गई छापेमारी के बाद महानगर के सैटेलाइट टाउनशिप स्थित एक आवासीय परिसर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार छह में से चार आरोपित चंदन मिश्रा हत्या में सीधे तौर पर शामिल थे। घटना के बाद वे पटना से भागकर कोलकाता आ गए थे।

उनके मोबाइल फोन टावर लोकेशन से हमें उनका पता लगाने में मदद मिली। अभी इन आरोपितों के नाम सामने नहीं आए हैं।

अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा, अमेरिका और दुबई से हो रही फंडिंग

यूपी पुलिस ने एक और अवैध धर्मांतरण गिरोह का किया भंडाफोड़

लखनऊ/एजेंसी

योगी सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार की पुलिस ने अवैध धर्मांतरण को रैकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ एक्शन के बाद एक और बड़े अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह प्रदेश में युवतियों को बरगलाकर, प्रलोभन देकर और कट्टरपंथी सोच के जरिए अवैध धर्मांतरण कराने में संलिप्त था। पुलिस ने गिरोह का

भंडाफोड़ करते हुए विभिन्न राज्यों से 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है।

अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा, अमेरिका और दुबई से हो रही फंडिंग

डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर में मिशन अस्मिता चलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को आगरा से दो सगी बहनों के लापता होने की सूचना मिली। पुलिस ने मामले की जांच कि तो अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल सामने आया। जांच में पता चला कि दोनों लड़कियों का ब्रेन वॉश कर अवैध धर्मांतरण किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक जाना शुरू किया। इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। डीजीपी ने बताया कि अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा, अमेरिका और दुबई समेत कई देशों से करोड़ों रुपये की अंतरराष्ट्रीय फंडिंग मिली थी, जिसका उपयोग देश में धार्मिक कट्टरता फैलाने और लड़कियों को बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने में किया जा रहा था। इनके तौर-तरीके, फंडिंग का दायरा और कार्यशैली आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों की तर्ज पर ही संचालित होती दिखीं। पुलिस ने जांच के दौरान छह राज्यों से 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है।

अवैध धर्मांतरण के आरोपियों को दबोचने के लिए बनायी गयीं सात टीमें

डीजीपी ने बताया कि आगरा से लापता लड़कियों के मामले की जांच की कमान पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को दी गयी। इस पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने मामले की जांच के लिए सात टीमें बनायीं। इस दौरान सर्विलांस, साइबर सेल से पुलिस को अहम जानकारियां मिलीं। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की। वहीं टीम को कोलकाता भेजा गया, जहां आगरा से लापता दोनों सगी बहनों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद उन्हे सुरक्षित किया गया। इसके बाद दोनों बहनों से विभिन्न जानकारी जुटाई गयी।

दिल्ली: मुखर्जी नगर से तीन बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

नई दिल्ली/एजेंसी

उत्तर-पश्चिमी जिले की विदेशी शाखा ने मुखर्जी नगर क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 14-15 जुलाई की रात को की गई। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपित दिल्ली में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे थे। जांच में पता चला है कि यह कबाड़ बीनने की आड़ में चोरी व अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। इनके मोबाइल फोन से प्रतिबंधित आईएमओ ऐप की मौजूदगी और बांग्लादेशी संपर्कों की पुष्टि होने पर इनकी जांच की गई। जिसमें यह बांग्लादेश के निवासी निकले।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at B B Graphic printer Z--57 Okhla Industrial Area ph.2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No DELENG/2013/54397